www.deshkiupasana.com
राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र
RNI NO - UPHIN/2022/86937
जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए
DKU LIVE
सब पर नज़र, सबकी ख़बर
वर्ष – 04 | अंक – 171 | जौनपुर गुरूवार, 05 फरवरी 2026 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

बुलडोजर कार्रवाई पर हाई कोर्ट का सवाल

प्रयागराज, (संवाददाता)। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश में किसी भी अपराध के बाद तत्काल बुलडोजर कार्रवाई किए जाने की प्रवृत्ति पर गंभीर सवाल उठाए हैं। हमीरपुर निवासी फहीमुद्दीन और दो अन्य को अंतरिम राहत देते हुए न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति सिद्धार्थनंदन की खंडपीठ ने पूछा कि क्या राज्य को किसी अपराधी के आवास को ध्वस्त करने का अधिकार है, या उसका दायित्व नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है? अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि अपराध के तुरंत बाद विध्वंस की कार्रवाई क्या कार्यपालक विवेक का विकृत प्रयोग खंडपीठ ने यह स्पष्ट किया कि यदि विध्वंस की 'उचित आशंका' भी हो, तो यह नागरिकों को अदालत की शरण लेने का पर्याप्त आधार प्रदान करती है।सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का भी उल्लेख किया और पूछा कि क्या इनका पालन किया जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने पहले स्पष्ट किया है कि किसी व्यक्ति को दंडित करने के लिए विध्वंस की कार्रवाई नहीं की जा सकती। दंड निर्धारित करना न्यायपालिका का अधिकार है, न कि कार्यपालिका का। राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी ने अदालत को आश्वस्त किया कि बिना विधिसम्मत प्रक्रिया का पालन किए और याचियों को अपना पक्ष रखने का अवसर दिए बिना कोई विध्वंस नहीं किया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई नौ फरवरी को निर्धारित की गई है।

खेल संघों के संचालन पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती

नई दिल्ली, (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने क्रिकेट और अन्य खेल संघों के संचालन पर गंभीर चिंता जताते हुए स्पष्ट कहा है कि खेल संस्थाओं का नेतृत्व ऐसे लोगों के हाथ में होना चाहिए जो खेल को समझते हों। कोर्ट ने टिप्पणी की कि क्रिकेट संघों में रिटायर्ड क्रिकेटरों को जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, न कि ऐसे लोगों को "जो बैट तक पकड़ना नहीं जानते।" मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के प्रस्तावित चुनाव पर रोक लगाई गई थी। यह चुनाव 6 जनवरी को होना था, लेकिन उस पर भाई–भतीजावाद और पक्षपात के आरोप लगे थे। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने MCA की सदस्यता में अचानक हुई बढ़ोतरी को लेकर कड़े सवाल उठाए। कोर्ट ने रिकॉर्ड का हवाला देते हुए कहा कि 1986 से 2023 तक एसोसिएशन में कुल 164 सदस्य थे। इसके बाद अचानक बड़ी संख्या में नए सदस्य जोड़े गए। CJI ने पूछा, "इतने वर्षों तक सदस्य संख्या सीमित रही और फिर अचानक यह 'बंपर ड्रॉ' कैसे हो गया?" उन्होंने कहा कि यदि सदस्य संख्या 300 तक बढ़ानी थी, तो उसमें नामी और सेवानिवृत्त अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को शामिल किया जाना चाहिए था।

प्रधानमंत्री मोदी ने शेयर किया संस्कृत सुभाषित, हंसी को बताया सबसे अच्छी दवा

नई दिल्ली, (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को प्राचीन ज्ञान पर आधारित एक प्रेरणादायक संदेश देशवासियों के साथ शेयर किया, जिसमें उन्होंने हंसी को सबसे अच्छी दवा बताया और इसके महत्व का जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सुभाषित शेयर करते हुए लिखा, औषधेष्वपि सर्वेषु हास्यं श्रेष्ठं वदन्ति है। स्वाधीनं सुलभं इस सुभाषित का संदेश है, कहा गया है कि सभी औषधियों में निश्चय ही हंसना श्रेष्ठ औषधि है, क्योंकि यह आसानी से बिना मूल्य के उपलब्ध हो जाती है व स्वास्थ्य और आनंद की वृद्धि करती है। अतः मुस्कुराते

रहें। 53 सेकेंड के वीडियो में इस संस्कृत सुभाषित का हिंदी और अंग्रेजी में अर्थ बताया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने दिसंबर 2025 से भारतीय परंपरा के कालजयी ज्ञान को आधुनिक नीति और जन–संवाद से जोड़ने के लिए समय–समय पर संस्कृत सुभाषित (प्रेरणादायक श्लोक) शेयर करना शुरू किया है। वे अक्सर अपने भाषणों, श्मन की बातश और सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से संस्कृत सुभाषित शेयर करते हैं। संस्कृत सुभाषितों को सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत करके प्रधानमंत्री मोदी समकालीन शासन को भारत की सभ्यतागत ज्ञान से सचेत रूप से जोड़ रहे हैं और प्राचीन श्लोकों का उपयोग विकास, स्थिरता, लैंगिक न्याय, नैतिक नेतृत्व और राष्ट्रीय उत्तरदायित्व जैसी आधुनिक प्राथमिकताओं को समझाने के लिए कर रहे हैं। पीएम मोदी ने 8 दिसंबर को भारत के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जीवन में संस्कृत की स्थायी प्रासंगिकता को रेखांकित किया। इसके साथ ही दूरदर्शन के सुप्रभातम कार्यक्रम में इसके दैनिक प्रसारण का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रत्येक सुबह इस कार्यक्रम में संस्कृत सुभाषित (ज्ञानपूर्ण उक्ति) प्रस्तुत की जाती है, जो मूल्यों और संस्कृति को एक साथ पिरोती है।

सीता मइया के दिव्य चरित्र का ज्ञान करायेगी वैदेही आर्ट गैलरी : सीएम योगी

लखनऊ, (संवाददाता)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रीअयोध्या धाम में माता सीता के जीवन–चरित्र पर केंद्रित श्वैदेही आर्ट गैलरीश की स्थापना के निर्देश दिए हैं। बुधवार को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की बैठक में उन्होंने कहा कि सीता मइया भारतीय संस्कृति, मर्यादा और नैतिक आदर्शों की अनुपम प्रेरणा हैं, और नई पीढ़ी को उनके उज्ज्वल चरित्र से गहराई से परिचित कराना समय की आवश्यकता है। आर्ट गैलरी की परिकल्पना साझा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अत्याधुनिक गैलरी केवल एक कला–संग्रहालय न होकर, सीता माता के जीवन, त्याग, करुणा, मर्यादा, धैर्य और शक्ति का आधुनिक तकनीक के माध्यम से पुनर्पाठ प्रस्तुत करने वाली एक जीवंत सांस्कृतिक अनुभव–स्थली होनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि इस गैलरी की कथा–वस्तु, डिजाइन,

विजुअल भाषा, कला और तकनीक सहित सभी आयाम इस भावना को प्रकट करे कि हम एक दिव्य विरासत का पुनर्पाठ कर रहे हैं, जिसे नई पीढ़ी के सामने प्रेरणास्रोत के रूप में स्थापित किया जाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैदेही आर्ट गैलरी की मूल भावना यही हो कि आगंतुक सीता माता के जीवन–संदेश को केवल देखें नहीं, बल्कि उसे अनुभव करें, समझें और आत्मसात करें। अयोध्या विकास प्राधिकरण के साथ संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निकट वशिष्ठ भवन परिसर में विकसित की जा सकती, जहां प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं।

राघव चड्ढा ने राज्यसभा में उठाया खाने में मिलावट का मुद्दा

नई दिल्ली, (एजेंसी)। आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने बुधवार को सदन में देश में खाने में मिलावट जैसे गंभीर मुद्दे को उठाया। उन्होंने इसे एक बड़ा स्वास्थ्य संकट बताया जो खासकर बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं के लिए गंभीर खतरा पैदा करता जा रहा है। आप सांसद राघव चड्ढा ने संसद में बोलते हुए कंपनियों पर सेहतमंद और एनर्जी बढ़ाने वाले झूठे दावों के तहत हानिकारक उत्पाद बेचने का आरोप लगाया। उन्होंने विस्तार से बताया कि कैसे रोजमर्रा की जरूरी चीजों में खतरनाक पदार्थ

मिलाए जाते हैं। उन्होंने बताया कि दूध खरीदिए, उसमें यूरिया मिलता है, सब्जियों में ऑक्सीटोसिन है, पनीर में स्टार्च और कास्टिक सोडा होता है, आइसक्रीम में डिटर्जेंट पाउडर मिलता है, फलों के जूस में सिंथेटिक फ्लेवर और आर्टिफिशियल रंग होते हैं, खाने के तेल में मशीन का तेल मिलाया जाता है, मसालों में ईंट का पाउडर और लकड़ी का बुरादा होता है, चाय में सिंथेटिक रंग मिलाए जाते हैं और पोल्ट्री उत्पादों में एनाबॉलिक स्टेरॉयड मिलाए जाते हैं। यहां तक घ्धकि देशी घी में जो मिठाइयां बनानी चाहिए, वो भी वनस्पति तेल और डालडा से बनाया जाता है। आप सांसद राघव चड्ढा ने आगे बताया कि एक मां अपने बच्चे को दूध का गिलास देती है, ये सोचकर कि उसके सेहत के लिए कैल्शियम और प्रोटीन मिलेगा और मेरा बच्चा दुरुस्त बनेगा। लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि वह अपने बच्चे को यूरिया और डिटर्जेंट मिला हुआ दूध पिला रही है। उन्होंने एक रिसर्च स्टडी का हवाला दिया।

अमेरिका से व्यापार समझौते पर देश में फैला रहे भ्रम : पीयूष गोयल

नई दिल्ली, (एजेंसी)। अमेरिका के साथ हुए व्यापार समझौते को लेकर केंद्र सरकार और कांग्रेस के बीच आरोप–प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणियों पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे देश में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं, भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला और उनके रवैये की तुलना पाकिस्तान और चीन से कर दी।मीडिया से बातचीत में पीयूष गोयल ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा अमेरिका–भारत व्यापार समझौते को लेकर लगाए गए आरोप तथ्यहीन हैं। उन्होंने कहा, "कांग्रेस नेता देश के सामने भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें भारत

के विकास और आर्थिक प्रगति से कोई लेना–देना नहीं है।" गोयल ने कहा कि यह समझौता भारत के आर्थिक हितों को मजबूत करने के लिए किया गया है और इससे निवेश, निर्यात तथा रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने सवाल किया, "क्या राहुल गांधी देश में हो रहे लाखों–करोड़ों रुपये के निवेश से परेशान हैं?उन्होंने कहा कि पीएम नरेन्द्र मोदी ने हमेशा कृषि और डेयरी दोनों सेक्टर को सपोर्ट किया है, उनके हितों की रक्षा की। जो लोग अलग–अलग सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं, खासकर ऐसे सेक्टर जिनमें ज्यादा मेहनत लगती है और जो लाखों लोगों को रोजगार देते हैं। गोयल ने कहा कि सभी इस डील से उत्साहित हैं। इसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प का धन्यवाद, उन्होंने पीएम मोदी की मित्रता का सम्मान किया। दोनों देश इस डील पर जल्द ही इस पर साझा बयान जारी करेंगे। इससे भारत का निर्यात बढ़ेगा। इससे हमारे इंजीनियरिंग सेक्टर्स के पार्ट्स बनाने वाले, टेक्सटाइल, मरीन गुड, ज्वेलर सेक्टर समेत सभी मैन्यूफेक्चरिंग सेक्टर को बहुत सारे मौके मिलेंगे।वाणिज्य मंत्री ने इस बात पर अफसोस जताया कि उन्हें संसद में इस महत्वपूर्ण व्यापार समझौते पर विस्तार से अपनी बात रखने का अवसर नहीं मिला। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस, द्रमुक, तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सांसदों ने सदन में हंगामा किया और चर्चा बाधित की। गोयल ने कहा, "विपक्षी नेताओं ने बेहद गैरजिम्मेदाराना व्यवहार किया।

सरदार सरोवर विस्थापितों के भूखंड का पंजीयन अब नि:शुल्क : मोहन यादव

भोपाल, (एजेंसी)। मध्य प्रदेश की मोहन कैबिनेट ने सरदार सरोवर परियोजना के विस्थापितों के संदर्भ में बड़ा फैसला लिया है। इसके मुताबिक अब इन विस्थापितों के लिए आवंटित भूखंडो का पंजीयन नि:शुल्क होगा।मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में नर्मदा घाटी की सरदार सरोवर परियोजना के विस्थापितों को आवंटित किए गए आवासीय भूखंडो का पंजीयन निशुल्क कराये जाने का निर्णय लिया गया। मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) अनुसार देय पंजीयन शुल्क एवं स्टॉम्प ड्यूटी की प्रतिपूर्ति नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा की जाएगी। इससे 25,600 से अधिक परिवारों को लाभ होगा। इस निर्णय से राज्य शासन पर 600 करोड़ रूपए का वित्तीय

भार आयेगा। मंत्रि–परिषद द्वारा मैहर एवं कटनी जिलें में 2 सिंचाई परियोजनाओं के लिए 620 करोड़ 65 लाख रूपए की स्वीकृति प्रदान की गई है।स्वीकृति अनुसार मैहर एवं कटनी की धनवाही सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना लागत 53 करोड़ 73 लाख रूपए की स्वीकृति दी गयी है। इससे 3500 हेक्टयर में सिंचाई की सुविधा प्राप्त होंगी और मैहर एवं कटनी जिले के 9 ग्राम के 2810 कृषक लाभान्वित होंगे। कटनी जिलें की बरही सूक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना लागत 566 करोड 92 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इससे, कटनी जिले की बरही एवं विजयराघवगढ़ तहसील के 27 ग्राम के 11,500 कृषक लाभान्वित होंगे और 20 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होंगी। मंत्रि–परिषद द्वारा 6 विभागों की 10 योजनाओं की वर्ष 2026–27 से वर्ष 2030–31 तक निरंतरता के लिए 15,009 करोड़ रूपए से अधिक की स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वीकृति अनुसार वित्त विभाग की लोक वित्त पोषित 500 करोड़ से कम की 8 योजनाओं के लिए 115 करोड़ 6 लाख रुपए, श्रम विभाग की मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल 2.0) योजना के लिए 5 हजार करोड़ रुपए, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की विधानसभा क्षेत्र निर्वाचन योजना और स्थापना एवं कार्यालयीन योजनाओं के लिए 3 हजार 376 करोड़ 66 लाख रूपए, पशु पालन एवं डेयरी विभाग की डॉ. भीमराव अम्बेडकर कामधेनु योजना, पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर ब्लॉकग्रांट योजना है।

राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र, राज्यपाल अभिभाषण पर हो सकती है बहस

जयपुर, (एजेंसी)। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र जारी है, जिसमें बुधवार को भी राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा जारी रहेगी। विधानसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे प्रश्नकाल से शुरू होगी, जिसमें विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर सवाल–जवाब किए जाएंगे। प्रश्नकाल के दौरान तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, आयुष, उद्योग एवं वाणिज्य, खेल और युवा मामले जैसे महत्वपूर्ण विभागों से जुड़े सवाल सदन में उठेंगे। विपक्ष सरकार से योजनाओं और नीतियों को लेकर जवाब मांगेगा, जबकि सरकार अपनी उपलब्धियों और आगे की रणनीति पेश करेगी। प्रश्नकाल में तारांकित प्रश्नों की सूची में 21 प्रश्न और अतारांकित प्रश्नों की सूची में 22 प्रश्न शामिल हैं। उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा से जुड़े विभागों, जैसे उद्योग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, जल संसाधन, जनजाति क्षेत्रीय विकास, राजस्व, नगरीय विकास और ऊर्जा विभाग से संबंधित सवालों पर चर्चा होगी। इन विभागों से जुड़ी विभिन्न योजनाओं और कार्यों को लेकर विधानसभा में सवाल उठाए जाएंगे। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा आपदा प्रबंधन सहायता व नागरिक सुरक्षा विभाग की 6 अधिसूचनाएं रखेंगे। इसके अलावा, सदन में कुछ महत्वपूर्ण अधिसूचनाएं भी रखी जाएंगी उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी वित्तीय विभाग से संबंधित 27 अधिसूचनाएं पेश करेंगी, वहीं, डॉ. प्रेमचंद बैरवा परिवहन विभाग की एक अधिसूचना प्रस्तुत करेंगे। इसके साथ ही, आपदा प्रबंधन सहायता और नागरिक सुरक्षा विभाग की छह अधिसूचनाएं गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म सदन में रखेंगे। गृह विभाग से सात अधिसूचनाएं भी पेश की जाएंगी। सदन में वार्षिक प्रतिवेदन भी रखे जाएंगे। उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी राजस्थान जन आधार प्राधिकरण का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी, जबकि मंत्री सुमित गोदारा राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट सदन में पेश करेंगे। राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस का सिलसिला कल एक दिन और बढ़ा दिया गया था, जिसे जारी रखा जाएगा।

संजय राउत ने भारत–अमेरिका व्यापार समझौते की आलोचना की

मुबई, (एजेंसी)। शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने गुरुवार को भारत–अमेरिका व्यापार समझौते की आलोचना की, जिसने पहले लागू 50 प्रतिशत टैरिफ को घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस व्यापार समझौते के जरिए अमेरिका ने लगभग भारत को खरीद लिया है। राउर ने कहा कि अमेरिका और भारत के बीच इस नए व्यापार समझौते से भारतीय किसानों की आर्थिक वृद्धि और खुशहाली को लेकर चिंता

व्यक्त की गई है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अब अमेरिका अपने कृषि उत्पादों को भारतीय किसानों के बाजार में सस्ते दामों पर बेच सकता है, जिसका सीधा असर भारतीय किसानों पर पड़ेगा।इस व्यापार समझौते से अमेरिका ने लगभग भारत को खरीद लिया है। वे इसे जीत कहते हैं, लेकिन यह कैसी जीत है? अब 18 प्रतिशत टैरिफ तय हो गया है, जो पहले 3 प्रतिशत था... अमेरिका से आने वाले कृषि उत्पाद भारतीय कृषि बाजार में 0 प्रतिशत टैरिफ के साथ प्रवेश करेंगे। इसमें सभी अनाज, फल और दुग्ध उत्पाद शामिल हैं। हमारे किसान दिन–रात मेहनत करके इन वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, और अब अमेरिका अपने उत्पादों को हमारे बाजार में कम कीमतों पर बेचेगा। फिर हमारे किसानों का क्या होगा? क्या वे आत्महत्या कर लेंगे...? ऐसा लगता है जैसे उन्होंने देश को बेच दिया हो...", उन्होंने कहा।भारत–अमेरिका व्यापार समझौते के तहत भारतीय वस्तुओं पर शुल्क घटाकर 18 प्रतिशत करने से देश में राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने कृषि और दुग्ध उत्पादन को संरक्षण दिए जाने के दावों पर सवाल उठाए हैं।

रेखा गुप्ता सरकार और प्राइवेट स्कूल लॉबी ने मिलकर कोर्ट में ड्रामा किया और सरकार ने सरेंडर कर दिया- सौरभ भारद्वाज

नई दिल्ली, (एजेंसी)। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने प्राइवेट स्कूल फीस कंट्रोल एक्ट को अभी भी मास्टर स्ट्रोक बता रही भाजपा सरकार को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने कहा कि रेखा गुप्ता सरकार और प्राइवेट स्कूल लॉबी ने मिलकर कोर्ट में ड्रामा किया और सरकार ने सरेंडर कर दिया। जिस प्राइवेट स्कूल एक्शन कमिटी ने कोर्ट में मुकदमा किया, वो भाजपा के दिल्ली शिक्षक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। भाजपा की सरकार बनते ही निजी स्कूलों ने 20–80 फीसद फीस बढ़ा दी। जब पैरेंट्स विरोध पर सड़क पर उतरे तो सरकार ने फीस कंट्रोल करने के लिए कानून लाने का उन्हें धोखा दिया। सरकार इस कानून को चोरी–छिपे लाई और बिना चर्चा

के ही लागू भी कर दिया। यह हास्यास्पद है कि जिस कानून से निजी स्कूलों में बढ़ी फीस को कम नहीं किया जा सकता, उसे शिक्षा मंत्री अभिभावकों की जीत बता रहे हैं।बुधवार को "आप" मुख्यालय पर प्रेस वार्ता कर सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली में 27 साल बाद जब भाजपा की रेखा गुप्ता सरकार बनी और आशीष सूद शिक्षा मंत्री बने, तो निजी स्कूलों वालों की जैसे लॉटरी लग गई। सरकार बनते ही लगभग सभी प्राइवेट स्कूलों ने 20 से लेकर 80 फीसद तक फीस बढ़ा दी, जिससे पूरी दिल्ली में हाहाकार मच गया। इसके विरोध में बच्चों के अभिभावकों ने धरने– प्रदर्शन किए, आशीष सूद और रेखा गुप्ता से मुलाकात की और सचिवालय तक में प्रदर्शन हुआ।सौरभ भारद्वाज ने कहा कि इसके जवाब में सरकार ने कहा कि वे फीस नियंत्रण के लिए एक शानदार कानून ला रहे हैं, लेकिन यह कानून चोरी–छिपे बनाया गया। आमतौर पर किसी भी कानून को जनता की राय के लिए वेबसाइट पर डाला जाता है और स्टेक होल्डर्स से सलाह ली जाती है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं किया गया। इसे चोरी–छिपे विधानसभा में लाया गया और बिना किसी चर्चा के पास कर दिल्ली की जनता पर थोप दिया गया। आम आदमी पार्टी ने तभी कहा था कि यह कानून बच्चों के लिए नहीं, बल्कि प्राइवेट स्कूल मालिकों की लॉबी और धन्ना सेठों की जेब गर्म करने के लिए लाया गया है।

संपादकीय

ट्रंप का भविष्य ट्रंप

ट्रंप की नीतियों ने विभिन्न देशों को नए साथी और नए अवसर ढूंढने के लिए मजबूर किया है। जब अमेरिका ने अपने साथ सम्मानजनक ढंग से कारोबार के रास्ते बंद कर दिए हैं, तो लाजिमी है, देश नए विकल्प की तलाश करेंगे। भारत और यूरोपियन यूनियन (ईयू) के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर सहमति बनने की खबर आते ही अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने ईयू को आगाह कि वह अपने खिलाफ युद्ध के लिए धन मुहैया कराने जा रहा है। कहा कि भारत रूस से कच्चा तेल खरीद कर उसे व्यापारिक सहारा देता है। यूरोप रूस के हमले की आशंका से पीड़ित है, लेकिन अब वह भारत को लाभ पहुंचाने जा रहा है। इसके पहले कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने चीन से व्यापार समझौता किया, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप भड़क गए। अपने चिर–परिचित अंदाज में कार्नी के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कनाडा पर 100 फीसदी टैरिफ लगाने की धमकी दी है। मगर अब कार्नी ने मार्च में भारत आने का इरादा जता दिया है। इसी बीच ट्रंप दक्षिण कोरिया पर भी खफा हो गए हैं और उस पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे–म्युंग ने इस महीने के पहले हफ्ते में चीन की यात्रा की थी। उनके बाद स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्लेलिन भी चीन गए और अब अगले मंगलवार को ब्रिटिश प्रधानमंत्री कियर स्टार्मर बीजिंग पहुंच रहे हैं। इस यात्रा से ठीक पहले ब्रिटिश सरकार ने लंदन में चीन के प्रस्तावित भव्य दूतावास के निर्माण को हरी झंडी दे दी, जिसे कई साल से रोक रखा गया था। उपरोक्त तमाम घटनाओं में एक समान तत्व की तलाश की जा सकती है। खुद ट्रंप प्रशासन की नीतियों ने विभिन्न देशों को नए साथी ढूंढने और नए अवसर तलाशने के लिए मजबूर किया है। जब अमेरिका ने अपने साथ सम्मानजनक ढंग से कारोबार के रास्ते बंद कर दिए हैं, तो लाजिमी है, विभिन्न देश नए विकल्प की तलाश करेंगे। लेकिन ऐसी हर घटना से ट्रंप की महत्त्वाकांक्षा पर आघात पहुंचता है। उससे व्यग्र होकर ट्रंप उग्र प्रतिक्रिया जताते हैं। लेकिन उससे वे विपरीत संदेश दुनिया को दे रहे हैं। हर विवेकशील देश इससे सोचने को मजबूर हो रहा है कि जब हर डील ट्रंप का भविष्य ट्रंप के मूड से जुड़ा है, तो आखिर उसके लिए कितनी हांव–पांव मारी जाए?

राष्ट्रीय सुरक्षा और राहुल गांधी की राजनीतिक अपरिपक्वता

ललित

नीति–निर्माण, राष्ट्रीय सुरक्षा और संसदीय विमर्श जैसे गंभीर विषय किसी भी लोकतंत्र की रीढ़ होते हैं। संसद केवल सत्ता और विपक्ष के टकराव का मंच नहीं, बल्कि राष्ट्रीय एकता, सामूहिक विवेक और जिम्मेदार अभिव्यक्ति का सर्वोच्च स्थल है। ऐसे में जब राष्ट्रपति के अभिभाषण जैसे संवैधानिक और गरिमामय अवसर पर चर्चा चल रही हो, तब किसी भी नेता से यह अपेक्षा स्वाभाविक है कि वह शब्दों, संदर्भों और समय–तीनों के प्रति अतिरिक्त सावधानी बरते। हालिया घटनाक्रम में लोकसभा में प्रतिनक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा पूर्व थलसेना प्रमुख जनरल एम. एम. नरवणे की अप्रकाशित पुस्तक के कुछ अंशों का हवाला देकर चीनी सेना की कथित घुसपैठ को लेकर जो बयान दिया गया, उसने इसी अपेक्षा पर प्रश्नचिह्न खड़े कर दिए। सरकार का आरोप रहा कि इस बयान ने लोकसभा को गुमराह करने का प्रयास किया, जबकि विपक्ष ने इसे सच दबाने की कोशिश बताकर पलटवार किया। परिणाम यह हुआ कि संसद की कार्यवाही बाधित हुई, तीखी बहस ने पूरे दिन का सत्र स्थगित करा दिया और राष्ट्रीय विमर्श का केंद्र मूल मुद्दों से हटकर आरोप–प्रत्यारोप बन गया। यह प्रश्न केवल एक वक्तव्य का नहीं, बल्कि राजनीतिक परिपक्वता, जिम्मेदारी और राष्ट्रीय हित की समझ का है। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विषयों पर सार्वजनिक वक्तव्यों में संवेदनशीलता अनिवार्य होती है। सीमाओं से जुड़े तथ्य, सैन्य तैनाती, रणनीतिक आकलन–ये सब ऐसे विषय हैं जिन पर आधे–अधूरे संदर्भ या चयनित उद्धरण अनावश्यक भ्रम पैदा कर सकते हैं। यही कारण है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने इसे संसदीय नियमों के उल्लंघन और राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ बताया। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था देने के बावजूद यदि किसी नेता का अपने वक्तव्य पर अड़े रहना कार्यवाही को ठप कर दे, तो सवाल उठता है कि क्या उद्देश्य सच सामने लाना था या राजनीतिक लाभ साधना। विपक्ष का दायित्व सत्ता से सवाल करना है, यह लोकतंत्र का प्राण है। किंतु सवालों की भाषा, मंच और समय–तीनों लोकतांत्रिक मर्यादाओं से बंधे होते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का समय सरकार की नीतियों, उपलब्धियों और भविष्य की दिशा पर समग्र विमर्श का होता है। उस दौरान सैन्य पुस्तकों के चयनित अंशों को राजनीतिक हथियार बनाना, वह भी बिना समुचित संदर्भ और संस्थागत प्रक्रिया के, स्वाभाविक रूप से विवाद को जन्म देता है। विपक्ष का यह कहना कि सरकार असहज प्रश्नों को दबाना चाहती है, एक परिचित एवं बेतूका राजनीतिक तर्क हैय परंतु सरकार का यह कहना कि राष्ट्रीय सुरक्षा को राजनीतिक रंग देना अनुचित है, उतना ही वजनदार प्रतिवाद है। दोनों पक्षों के बीच संतुलन वहीं संभव है, जहां तथ्य, प्रक्रिया और समय का सम्मान हो। संसद के भीतर अप्रकाशित 'संस्मरण' के जिक्र पर विवाद होना स्वाभाविक है। क्योंकि संसदीय परंपराओं और स्थापित नियमों के अनुसार किसी भी सदस्य द्वारा संसद के पटल पर ऐसी प्रकाशित या अप्रकाशित पुस्तक, लेख या पत्रिका की सामग्री को प्रमाण के रूप में उद्धृत करना स्वीकार्य नहीं है, जिसे सदन के समक्ष औपचारिक रूप से प्रस्तुत (टेबल) न किया गया हो। विशेष रूप से ऐसी पुस्तकों या लेखों के अंश, जिनकी न तो संसदीय सत्यापन प्रक्रिया हुई हो और न ही जिन्हें सदन की अनुमति से अभिलेखित किया गया हो, उन्हें तथ्यात्मक प्रमाण मानना संसदीय मर्यादा के विरुद्ध है। इस दृष्टि से राहुल गांधी द्वारा किसी अप्रकाशित पुस्तक के अंशों को सीध ा उद्धृत कर उन्हें नीतिगत या राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर अंतिम सत्य के रूप में प्रस्तुत करना न केवल संसदीय नियमों की अवहेलना है, बल्कि इससे सदन की गरिमा और कार्यवाही की विश्वसनीयता भी आहत होती है। राहुल गांधी केवल कांग्रेस के नेता ही नहीं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। कम से कम राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में तो उन्हें भारतीय सेनाओं के नैरेटिव के साथ खड़े होना चाहिए। दुर्भाग्य से वे ऐसा नहीं करते। वे चीन और पाकिस्तान को लेकर मोदी सरकार को तो घेरते हैं, लेकिन यह स्मरण नहीं रखते कि इन दोनों देशों ने भारतीय भूभाग पर तब अतिक्रमण किया, जब कांग्रेस सत्ता में थी। गलवान में चीनी सेना के साथ खूनी टकराव के मामले में तत्कालीन सेनाध्यक्ष की अप्रकाशित पुस्तक के कथित अंश का जैसा उल्लेख राहुल गांधी ने किया, उस पर हंगामा होना ही था। आखिर जो पुस्तक प्रकाशित ही नहीं हुई, उसका उल्लेख राहुल कैसे कर सकते हैं? राहुल गांधी का आरोप कि मोदी सरकार ने चीनी सेना के अतिक्रमणकारी रवैये पर साहस नहीं दिखाया, बेबुनिया एवं भ्रमित करने वाला आरोप है। यह पहली बार नहीं है, जब राहुल गांधी ने यह कहने की कोशिश की हो कि प्रधानमंत्री मोदी चीन का डटकर मुकाबला करने से बचते हैं। वे मोदी सरकार को कमजोर दिखाने के लिए यह भी कहते रहे हैं कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर रखा है। वे यहां तक कह चुके हैं कि चीनी सेना ने भारतीय सैनिकों की पिटाई की थी। इसके लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट की फटकार भी सुननी पड़ी थी। इसके बाद भी वे यह समझने के लिए तैयार नहीं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में सतही आरोपों के आधार पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। जबकि सच्चाई यह है और सब जानते हैं कि गलवन में चीनी सेना को करारा जवाब मिला था और इसी कारण वह वार्ता की मेज पर आया और लद्दाख में कई इलाकों में यथास्थिति कायम हो पाई। कांग्रेस की भूमिका पर भी गंभीर आत्ममंथन आवश्यक है। एक समय देश को नेतृत्व देने वाली पार्टी आज बार–बार ऐसे प्रसंगों में उलझती दिखती है, जहां बयानबाजी मुद्दों पर भारी पड़ जाती है। राहुल गांधी एक प्रभावशाली वक्ता हैं, जनभावनाओं को छूने की क्षमता रखते हैं और युवाओं में संवाद स्थापित कर सकते हैं। किंतु यही

कारण है कि उनसे अधिक जिम्मेदारी की अपेक्षा भी की जाती है। बार–बार ऐसे मुद्दे उठाना जिन्हें सत्ता पक्ष राष्ट्रीय एकता के लिए घातक बताता हो, कांग्रेस की छवि को गैर–जिम्मेदार विपक्ष के रूप में मजबूत करता है। यह धारणा चाहे पूरी तरह सही न हो, लेकिन राजनीति में धारणा भी उतनी ही प्रभावशाली होती है जितना तथ्य। तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो परिपक्व लोकतंत्रों में राष्ट्रीय सुरक्षा पर बहस के लिए अलग–अलग संसदीय समितियां, बंद सत्र और संस्थागत प्रक्रियाएं होती हैं। सार्वजनिक मंचों पर बयान देते समय नेता प्रायः संकेतों और नीतिगत प्रश्नों तक सीमित रहते हैं, विस्तृत सैन्य विवरणों से परहेज करते हैं। भारत में भी ऐसी परंपरा विकसित होनी चाहिए, जहां विपक्ष सरकार से जवाबदेही मांगे, परंतु सेना और सुरक्षा संस्थानों की साख को राजनीतिक संघर्ष का अखाड़ा न बनाया जाए। यही संतुलन लोकतंत्र को मजबूत करता है। लेकिन राहुल गांधी पूर्व में भी सैन्य बयानों से न केवल सुरक्षा के लिये खतरा बनते रहे हैं बल्कि हमारे जवानों के मनोबल को भी आहत करते रहे हैं। यह भी सच है कि सरकार को पारदर्शिता से घबराना नहीं चाहिए। यदि विपक्ष किसी पुस्तक, रिपोर्ट या बयान का हवाला देता है, तो उसका संस्थागत और तथ्यपरक उत्तर दिया जाना चाहिए। केवल नियमों के उल्लंघन का हवाला देकर बहस को समाप्त करना भी स्वस्थ परंपरा नहीं कही जा सकती। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर पूर्ण मौन भी लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व के विपरीत है। अतः दोनों पक्षों को अपनी–अपनी सीमाएं पहचाननी होंगी। अंततः प्रश्न राहुल गांधी की परिपक्वता का भी है। परिपक्वता का अर्थ चुप रहना नहीं, बल्कि यह समझना है कि कौन–सा प्रश्न कब, कहां और कैसे उठाया जाए। एक राष्ट्रीय नेता से अपेक्षा होती है कि वह भावनात्मक आवेग के बजाय रणनीतिक विवेक से काम ले। इसी तरह विपक्ष की सामूहिक जिम्मेदारी है कि वह संसद को ठप करने के बजाय उसे प्रभावी बहस का मंच बनाए।

भारत वसुधैव कुटुम्बकम के भाव के साथ मुक्त व्यापार समझौते सम्पन्न कर रहा है

प्रह्लाद

दिनांक 27 जनवरी 2026 को यूरोपीय यूनियन के 27 सदस्य देशों के साथ भारत ने एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया है। अब, इस समझौते की शर्तों को इन देशों की संसद द्वारा पारित किया जाएगा, इसके बाद यह मुक्त व्यापार समझौता यूरोपीय यूनियन एवं भारत के बीच होने वाले विदेशी व्यापार पर लागू हो जाएगा। इस मुक्त व्यापार समझौते को "मदर आफ ऑल डील्स" कहा जा रहा है। क्योंकि, यह मुक्त व्यापार समझौता विश्व के 28 देशों के उस भूभाग पर लागू होने जा रहा है, जहां विश्व की 30 प्रतिशत आबादी निवास करती है। पृथ्वी के इस भूभाग पर 200 करोड़ से अधिक नागरिकों का निवास है। इन 28 देशों की संयुक्त रूप से विश्व के कुल सकल घरेलू उत्पाद में 25 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी (संयुक्त रूप से) अर्थव्यवस्था (यूरोपीय यूनियन – 22 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर) एवं चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था (भारत – 4 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर) के बीच यह मुक्त व्यापार समझौता सम्पन्न होने जा रहा है। वैश्विक स्तर पर होने वाले विदेशी व्यापार में इन समस्त देशों की हिस्सेदारी 33 प्रतिशत है। पूरी दुनिया में 33 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर का विदेशी व्यापार होता है, इसमें से 11 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर का विदेशी व्यापार उक्त 28 देशों द्वारा किया जाता है। उक्त वर्णित मुक्त व्यापार समझौता विश्व का सबसे बड़ा व्यापार समझौता है। इसके पूर्व, सबसे बड़े मुक्त व्यापार समझौते के रूप में चीन एवं 10 आशियान देशों के बीच सम्पन्न हुए मुक्त व्यापार समझौते को माना जाता है। यह केवल एक मुक्त व्यापार समझौता नहीं बल्कि यूरोपीय यूनियन के 27 देशों एवं भारत के बीच साझा समृद्धि का एक ब्लूप्रिंट है। इस समझौते में पूरी दुनिया की आर्थिक दशा एवं दिशा बदलने की क्षमता है। उक्त व्यापार समझौता को सम्पन्न करने के प्रयास पिछले 18 वर्षों से हो रहे थे। परंतु, कुछ विपरीत परिस्थितियों के चलते इस समझौते को सम्पन्न होने में इतना लम्बा समय लग गया है, अतः यह अब भारत एवं यूरोपीय यूनियन के 27 देशों के बीच एक नए युग की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। उक्त मुक्त व्यापार समझौते के सम्पन्न होने के पश्चात वर्ष 2032 तक यूरोपीयन यूनियन के सदस्य देशों एवं भारत के बीच विदेशी व्यापार के दुगना होने की सम्भावना व्यक्त की जा रही है। इसके पूर्व भारत एवं यूनाइटेड किंगडम के बीच भी मुक्त व्यापार समझौता सम्पन्न किया जा चुका है। अब कनाडा के प्रधानमंत्री भी संभवतरू मार्च माह में भारत के दौरे पर आने वाले है और भारत एवं कनाडा के बीच भी कुछ क्षेत्रों में व्यापार समझौता सम्पन्न होने की सम्भावना व्यक्त की जा रही है। अमेरिका मुक्त व्यापार समझौतों को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जबकि भारत मानवतावादी दृष्टिकोण को अपनाते हुए विभिन्न देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते कर रहा है ताकि भारत एवं अन्य समस्त देशों में निवासरत नागरिकों को इन समझौतों से लाभ मिले। यह भारतीय संस्कृति के वसुधैव कुटुम्बकम के भाव को दर्शाता है। भारत की इस नीति के चलते ही विश्व के कई देश अब भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते शीघ्र ही सम्पन्न करना चाह रहे हैं। वैश्विक स्तर पर हाल ही के समय में आर्थिक क्षेत्र में भारी उथल पुथल दिखाई दे रही है। भारत एवं यूरोपीय यूनियन के 27 सदस्य देशों के बीच सम्पन्न हुए मुक्त व्यापार समझौते से इस उथल पुथल में कुछ सुधार आता हुआ दिखाई देगा। भारत में कृषि एवं डेयरी क्षेत्र अतिसंवेदनशील है। क्योंकि, भारत की कुल आबादी का लगभग 60 प्रतिशत भाग आज भी ग्रामीण इलाकों में उक्त क्षेत्रों पर अपनी आजीविका के लिए निर्भर है। अतः उक्त दोनों क्षेत्रों को मुक्त व्यापार समझौते से बाहर रखा गया है। हां, भारत के समुद्री उत्पाद उद्योग, वस्त्र एवं परिधान उद्योग, जेम्स एवं ज्वेलरी उद्योग, चमड़ा उद्योग, खिलौना उद्योग जो श्रम आधारित उद्योग हैं, को उक्त मुक्त व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ होगा क्योंकि यूरोपीय यूनियन के समस्त 27 देशों द्वारा भारत से उक्त उत्पादों के आयात पर आयात ड्यूटी को शून्य किया जा रहा है। वर्तमान में भारत से समुद्रीय उत्पादों के निर्यात पर 26 प्रतिशत का आयात कर लगाया जाता है, जिसे मुक्त व्यापार समझौता के लागू होने के पश्चात शून्य कर दिया जाएगा। इसी प्रकार, वस्त्र एवं परिधान के आयात पर वर्तमान में लागू 12 प्रतिशत के आयात कर को शून्य किया जा रहा है, खिलौना पर लागू 4.7 प्रतिशत के आयात कर को शून्य, जेम्स एवं ज्वेलरी के आयात पर 4 प्रतिशत से शून्य, केमिकल उत्पादों के आयात पर 12.8 प्रतिशत से शून्य, चमड़ा से निर्मित उत्पादों के आयात पर 17 प्रतिशत से शून्य, फर्नीचर उत्पादों के आयात पर 10.7 प्रतिशत से शून्य आयत कर किया जा रहा है। यूरोपीय यूनियन के 27 देश, जो विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हैं, में जन्म दर पिछले कई वर्षों से लगातार गिर रही है एवं कुछ देशों में तो यह शून्य के स्तर पर पहुंच गई है जिससे इन देशों में प्रौढ़ नागरिकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। सेवा क्षेत्र में कार्य करने वाले नागरिकों का इन देशों में नितांत अभाव दिखाई देता है। अतः इन देशों में श्रमबल की भारी कमी है। उक्त मुक्त व्यापार समझौते के सम्पन्न होने के पश्चात भारतीय नागरिकों को यूरोपीय यूनियन के समस्त 27 देशों में तकनीकी क्षेत्र, चिकित्सा क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, आदि में रोजगार के भारी मात्रा में अवसर प्राप्त होंगे। इन समस्त देशों द्वारा भारतीय नागरिकों को वीजा प्रदान करने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। युनाईटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रान्स आदि जैसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं जैसे देशों में भारतीय इंजिनीयरों एवं डाक्टरों की भारी मांग है। उक्त देशों द्वारा भारतीयों के परिवार के सदस्यों को रोजगार प्रदान करने के अवसर भी प्रदान करने सम्बंधी प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। भारतीय विद्यार्थियों द्वारा यूरोपीय यूनियन के सदस्य देशों के विश्वविद्यालयों में अपनी शिक्षा समाप्त करने के उपरांत 9 माह से 12 माह तक का समय रोजगार तलाशने के लिए प्रदान किया जाएगा। इस समयावधि तक भारतीय युवाओं को इन देशों में प्रवास की अनुमति प्रदान की जाएगी। भारतीय कारीगरों के लिए अब वैश्विक बाजार खुल रहा है। साथ ही, भारत अब विनिर्माण इकाईयों का वैश्विक केंद्र बन सकता है। क्योंकि, यूरोपीयन यूनियन के समस्त देश विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हैं एवं वे अपनी सम्पत्तिध्पूंजी का निवेश भारत में विनिर्माण इकाईयों में कर सकते हैं एवं कुछ लाभप्रद क्षेत्रों में वे अपनी विनिर्माण इकाईयों की स्थापना भी कर सकते हैं।

सस्ती तकनीक और हर नागरिक तक पहुंच – एआई में आत्मनिर्भर भारत की तैयारी

सुशील पाल

कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई आज की सबसे ताकतवर और तेजी से बदलने वाली तकनीक में से एक बनती जा रही है। इसमें यह क्षमता है कि यह देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे, उत्पादन बढ़ाए और विकास की रफ्तार तेज करे। सरकारी सेवाओं को ज्यादा प्रभावी और पारदर्शी बनाने में भी एआई अहम भूमिका निभा सकती है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बीमारी की शुरुआती पहचान, खेती में सही समय पर सही फैसले लेने, आपदा से पहले चेतावनी देने, मौसम और जलवायु का बेहतर अनुमान लगाने और सरकारी योजनाओं का लाभ आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने में एआई पहले से ही मदद कर रही है। आने वाले समय में शिक्षा, परिवहन और उद्योग जैसे क्षेत्रों में भी एआई का इस्तेमाल तेजी से बढ़ने की संभावना है। लेकिन जैसे पहले की तकनीकी क्रांतियों में हुआ, वैसे ही एआई के साथ भी असमानता की तस्वीर सामने आती है। जिनके पास कंप्यूटर की ताकत यानी कंप्यूट, अच्छा डेटा और मजबूत डिजिटल ढांचा है, वही बड़े स्तर पर एआई का लाभ उठा पा रहे हैं। जिनके पास ये सुविधाएं नहीं हैं, वे पीछे रह जाते हैं। यह फर्क आज केवल कंपनियों के बीच ही नहीं, बल्कि देशों और इलाकों के बीच भी साफ दिखाई देता है। भारत ने इस चुनौती को एक अवसर के रूप में लिया है। इंडिया एआई मिशन के जरिए भारत यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि एआई की ताकत कुछ गिने–चुने लोगों तक सीमित न रहे। कंप्यूट, डेटा और एआई मॉडल को डिजिटल सार्वजनिक सुविधा के रूप में देखा जा रहा है, ताकि स्टार्टअप, शोधकर्ता, छात्र और छोटे संस्थान भी एआई पर काम कर सकें। भारत की सोच साफ है– ऐसा डिजिटल ढांचा बनाया जाए जो खुला हो, आसानी से बढ़ सके और समाज के हर वर्ग के काम आए। इससे एआई का लाभ आम लोगों तक पहुंचे, देश में ही नवाचार को बढ़ावा मिले और तकनीक के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बन सके। इस सोच के पीछे एक ठोस योजना है। दावोस में हुए विश्व आर्थिक मंच में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि भारत एआई को पांच स्तरों पर विकसित कर रहा है– बिजली और ऊर्जा, कंप्यूट और इंफ्रास्ट्रक्चर, चिप और हार्डवेयर, एआई मॉडल और एप्लिकेशन। इन सभी पर एक साथ काम होने से ही एआई का सही और व्यापक उपयोग संभव हो पाएगा। भारत का तरीका इसलिए अलग है क्योंकि यहां एआई तक पहुंच आसान बनाई गई है। भारत ने एक साझा कंप्यूट प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जहां 38,000 जीपीयू एक ही पोर्टल पर मिलते हैं। इनका खर्च करीब 65 रुपये प्रति घंटा है, जबकि दूसरे देशों में इसके लिए 2.5 से 3 डॉलर प्रति घंटा तक देने पड़ते हैं। इंडिया एआई मिशन के तहत सरकार एआई मॉडल बनाने के लिए पूरी लागत (100 प्रतिशत) तक मदद दे रही है और एआई के इस्तेमाल पर भी 40 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है। इससे पैसे की कमी एआई पर काम करने में रुकावट नहीं बनती। इसी वजह से सरवम एआई, सोकेट एआई और ज्ञानि एआई जैसे भारतीय स्टार्टअप अब बिना बड़ी पूंजी लगाए अपने खुद के एआई और भाषा मॉडल बना पा रहे हैं, जो पहले सिर्फ बड़ी विदेशी कंपनियां ही कर पाती थीं। भारत का लक्ष्य सिर्फ एआई का इस्तेमाल करना नहीं, बल्कि अपना एआई बनाना है। भारत अपना खुद का एआई मॉडल तैयार कर रहा है, जो भारतीय भाषाओं, भारतीय संस्कृति और भारतीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। इसे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट (16–20 फरवरी 2026) में पेश किए जाने की उम्मीद है। यह मॉडल भारत के ही डेटा पर प्रशिक्षित होगा और देश के भीतर ही काम करेगा। इससे एआई ज्यादा सटीक, निष्पक्ष और सबको साथ लेकर चलने वाला बनेगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित होगा कि डेटा सुरक्षित रहे और एआई का इस्तेमाल देश के कानूनों और नागरिकों के अधिकारों के अनुसार हो। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में एआई को लेकर केवल जोखिमों की चर्चा नहीं होगी, बल्कि यह देखा जाएगा कि एआई जमीन पर क्या बदलाव ला रही है। इसमें एआई को सबके लिए उपलब्ध कराने, विकास में इसके उपयोग, पर्यावरण की रक्षा, भरोसेमंद सिस्टम, भारतीय भाषाओं में एआई, ग्लोबल साउथ की भागीदारी और एआई से जुड़ी असमानताओं को कम करने जैसे मुद्दों पर विचार किया जाएगा।

राष्ट्र निर्माण के प्रति कर्तव्य: वह बजट जो भारत के भविष्य को आकार देगा

तोखन साहू

वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया केंद्रीय बजट 2026–27, सिर्फ एक सालाना वित्तीय बयान से कहीं ज्यादा हैय यह एक विकसित भारत बनाने का ब्लूप्रिंट है। माघ पूर्णिमा के पवित्र अवसर और गुरु रविदास जी की जयंती पर पेश किया गया यह बजट एक गहरे नैतिक और राष्ट्रीय उद्देश्य को दर्शाता है। ऐतिहासिक 53.5 लाख करोड़ के कुल खर्च और लगभग 27 लाख करोड़ के पूंजीगत खर्च के साथ, यह बजट राजकोषीय समझदारी बनाए रखते हुए भारत की विकास गाथा में विश्वास का संकेत देता है, जिसमें घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 4.3त्न पर सीमित है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह युवा भारतीयों की आकांक्षाओं को दर्शाता है, जिनके विचार प्रधानमंत्री के विकसित भारत युवा नेता संवाद के दौरान साझा किए गए थे और उन्हें राष्ट्रीय नीति निर्माण में जगह मिली है। यह विकास सिर्फ दफ्तरों में नहीं, बल्कि नागरिकों के साथ बातचीत के जरिए आकार दिया गया है। 3 कर्तव्यों से प्रेरित और हमारे युवाओं की आकांक्षाओं से निर्देशित, यह बजट विकास और समावेश, महत्वाकांक्षा और करुणा के बीच संतुलन बनाता है। पहला कर्तव्य आर्थिक विकास को तेज करने और बनाए रखने पर केंद्रित है, जो एक विकसित अर्थव्यवस्था की नींव रखेगा। 10,000 करोड़ का बायोफार्मा मिशन, सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, और महत्वपूर्ण खनिजों, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, कंटेनर उत्पादन और मेगा टेक्सटाइल पार्क को मजबूत करने के उपाय घरेलू उद्योग को बढ़ावा देंगे और आयात पर निर्भरता कम करेंगे। ये दूरदर्शी क्षेत्र भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में मजबूती से स्थापित करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का इंजन को एक बड़ा बढ़ावा मिला है, जिसमें फ्रेट कॉरिडोर, जलमार्ग और मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए सार्वजनिक पूंजीगत व्यय में 12.2 लाख करोड़ का प्रावधान है। शहरी आर्थिक क्षेत्र, हाई–स्पीड रेल कॉरिडोर और म्युनिसिपल बॉन्ड प्रोत्साहन शहरों को उत्पादकता के केंद्र बनाएंगे, लॉजिस्टिक्स लागत कम करेंगे, निवेश आकर्षित करेंगे और बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करेंगे। दूसरा कर्तव्य लोगों के सशक्तिकरण को प्राथमिकता देता है। हेल्थकेयर संस्थानों में निवेश, संबद्ध स्वास्थ्य कार्यबल का विस्तार, और बुजुर्गों की देखभाल सेवाएं सामाजिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करती हैं। यूनिवर्सिटी टाउनशिप और हर जिले में महिलाओं के हॉस्टल जैसी शिक्षा पहल पहुंच और सुरक्षा में सुधार करती हैं, जबकि पर्यटन, विरासत विकास और खेलो इंडिया मिशन युवाओं के लिए नए अवसर खोलते हैं। तीसरा कर्तव्य, सबका साथ, सबका विकास के मार्गदर्शन में, समावेशी विकास सुनिश्चित करता है। किसानों को मत्स्य पालन, पशुधन और उच्च मूल्य वाली कृषि के साथ–साथ जल निकायों के विकास के माध्यम से सहायता मिलती है। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल में निवेश और पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए केंद्रित पहल संतुलित क्षेत्रीय प्रगति को बढ़ावा देती हैं। यह दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि भारत की विकास यात्रा में कोई भी समुदाय या क्षेत्र पीछे न छूटे। छत्तीसगढ़ के लिए यह बजट अवसरों का एक नया अध्याय खोलता है। भारत को ग्लोबल बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए प्रस्तावित ?10,000 करोड़ के निवेश से राज्य को फायदा होगा, जिससे राज्य में निवेश, रिसर्च और हाई–क्वालिटी नौकरियों के अवसर आएंगे। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 में शामिल होने से छत्तीसगढ़ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरने में मदद मिलेगी। प्रोसेसिंग यूनिट्स स्थापित करके, राज्य ओडिशा के साथ मिलकर रेयर मेटल कॉरिडोर से रणनीतिक और औद्योगिक रूप से भी लाभ उठा सकता है। टेक्सटाइल सेक्टर में पहल – जिसमें नेशनल फाइबर मिशन, टेक्सटाइल विस्तार और रोजगार योजना, और मेगा टेक्सटाइल पार्क शामिल हैं – छत्तीसगढ़ के पारंपरिक शिल्प, हथकरघा, खादी और आधुनिक टेक्सटाइल उद्योगों को नई गति देंगे। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी और स्थानीय कारीगरों की आय बढ़ाएगी। एमएसएमई के लिए बजटीय सहायता यह सुनिश्चित करेगी कि राज्य में छोटे और मध्यम उद्यमों को अधिकतम लाभ मिले, जिससे स्वरोजगार और स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन और स्टोरेज के लिए 20,000 करोड़ का प्रावधान छत्तीसगढ़ को अपने समृद्ध वन संसाधनों को कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग के जरिए आर्थिक लाभ में बदलने का अवसर देता है। शिक्षा के क्षेत्र में, राज्य में कम से कम एक यूनिवर्सिटी टाउनशिप की स्थापना और हर जिले में एक महिला छात्रावास उच्च शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक समावेश को मजबूत करेगा। हर जिले में ट्रॉमा सेंटर की स्थापना, बुजुर्गों की देखभाल सेवाओं का विस्तार, और राज्य में एक अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित करने के प्रयासों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा। टियर–2 और टियर–3 शहरों में कॉर्पोरेट फैसिलिटेटर की शुरुआत से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा। मछली पालन, अमृत सरोवरों के इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, पशुपालन, डेयरी और पोल्ट्री फार्मिंग, और हाई–वैल्यू एग्रीकल्चर के लिए सपोर्ट से किसानों की आय बढ़ेगी, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। खेलो इंडिया मिशन के जरिए, छत्तीसगढ़ के एथलीटों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने के अवसर मिलेंगे। शहरी विकास के लिए, अर्बन इकोनॉमिक रीजन्स के लिए 5,000 करोड़ का आवंटन और म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने के लिए प्रोत्साहन छत्तीसगढ़ के शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक क्षमता को मजबूत करेगा। नए इनकम टैक्स एक्ट, आसान टैक्स नियमों, टीडीएसध्टीसीएस के युक्तिकरण, और कस्टम ड्यूटी में राहत जैसे सुधार टैक्स सिस्टम को नागरिकों, उद्योगों और निवेशकों के लिए ज्यादा पारदर्शी, सरल और निष्पक्ष बनाएंगे।

सेवानिवृत आईजी को भी एसआईआर का नोटिस

लखनऊ, (संवाददाता)। एसआईआर प्रक्रिया के तहत सेवानिवृत्त आईजी जैसे विशिष्ट नागरिक को भी नोटिस थमा दिया गया है। मंगलवार को बारिश के बीच 78 वर्षीय रिटायर्ड आईजी (फायर सर्विस) अभय शंकर सुनवाई के लिए विकास भवन पहुंचे। विडंबना यह रही कि भवन की लिफ्ट खराब होने के कारण उन्हें बुजुर्ग अवस्था में भी तीसरी मंजिल तक सीढ़ियों के सहारे पहुंचना पड़ा। इंदिरानगर निवासी अभय शंकर ने बताया कि उन्होंने आवेदन के समय मतदाता पहचान पत्र लगाया था, लेकिन वर्ष 2003 की मतदाता सूची से उसका मिलान न होने के कारण उन्हें नोटिस जारी कर दिया गया। उन्होंने सभी जरूरी कमियां पूरी कर दी हैं। वहीं, उद्यान विभाग के कर्मचारी बी. देवेंद्र को भी नोटिस मिला, जिनका कहना था कि 2003 में वह नाबालिग थे, उसी वर्ष उनके पिता का निधन हो जाने के कारण उनका भी नाम मतदाता सूची में नहीं था। मां का नाम था, जिसके अभिलेख लगाए थे, फिर भी नोटिस मिला। मंगलवार को सुबह से हो रही बारिश के कारण सुनवाई केंद्रों पर सन्नाटा पसरा रहा। विकास भवन में जिला समाज कल्याण अधिकारी ने 447 लोगों को बुलाया था, लेकिन केवल 65 लोग ही पहुंच सके। वहीं, हुसैनाबाद ट्रस्ट में सुनवाई कर रहे जिला कृषि अधिकारी तेगबहादुर सिंह ने 300 लोगों को नोटिस दिया था, लेकिन यहां भी संख्या बेहद कम रही। जिले में मतदाता सूची से जुड़े सत्यापन अभियान के तहत अब तक 8,99,781 नोटिस जारी करने का लक्ष्य तय किया गया है, जिसमें मंगलवार तक 4,61,025 लोगों को नोटिस जनरेट किया जा चुका है। इनमें से 2,89,316 नोटिस संबंधित व्यक्तियों तक पहुंचाए भी जा चुके हैं, जबकि 1,71,709 नोटिस अभी वितरण के लिए लंबित हैं। सबसे अधिक नोटिस बख्शी का तालाब, सरोजनीनगर और लखनऊ पश्चिम विधानसभा क्षेत्रों में जनरेट हुए हैं। जिले में अब तक 93,502 मामलों में सुनवाई पूरी हो चुकी है, जबकि 1,47,550 मामलों में सुनवाई की तारीख निकल चुकी (डेट लैप्स) दर्ज है। री–शेड्यूल (पुनर्निर्धारित) सुनवाई की संख्या 465 बताई गई है। लखनऊ पश्चिम में सबसे ज्यादा 22,227 सुनवाई हुई हैं, जबकि बख्शी का तालाब में 14,011 और लखनऊ उत्तर में 10,824 मामलों में सुनवाई दर्ज की गई। अधिकारियों का कहना है कि लंबित मामलों को प्राथमिकता पर निपटाया जा रहा है।

खेत में काम कर रहे सगे भाइयों पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला

लखनऊ, (संवाददाता)। गोंडा जिले के करनैलगंज कोतवाली के नरायनपुर माझा मजरा दुल्हिन पुरवा गांव में मंगलवार की रात खेत में काम कर रहे दो सगे भाइयों पर अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में एक भाई की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा भाई गंभीर रूप से घायल है। जानकारी के अनुसार शिवशंकर उर्फ लल्ला दुबे (32) और उनके भाई अमरनाथ मंगलवार देर शाम अपने खेत में काम कर रहे थे। तभी आए हमलावरों ने पहले लल्ला पर जानलेवा हमला कर दिया। भाई को लहूलुहान देख अमरनाथ उसे बचाने दौड़े तो हमलावरों ने उन पर भी वार कर दिया। दोनों भाइयों को खून से लथपथ छोड़कर हमलावर मौके से फरार हो गए। घटना के बाद अमरनाथ की चीख–पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण दौड़े। आनन–फानन में घायल अमरनाथ को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां से हालत नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने जिला अस्पताल गोंडा रेफर कर दिया। वारदात की सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल के साथ अपर पुलिस अधीक्षक देर रात मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया। फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एएसपी ने बताया कि घटना की हर पहलू से गहन जांच की जा रही है।

संक्षिप्त खबरें

पं. बिरजू महाराज की जयंती पर दो दिवसीय समारोह

लखनऊ, (संवाददाता)। महान कथक आचार्य पद्मविभूषण पं. बिरजू महाराज की जयंती पर दो दिवसीय समारोह का आयोजन बुधवार से बिरजू महाराज कथक संस्थान की ओर से किया जा रहा है। पहले दिन 'नाट्यशास्त्र और समकालीन शास्त्रीय नृत्य विधाएं' विषय पर व्याख्यान का आयोजन भातखंडे संस्कृति विवि के जयशंकर सभागार में किया जाएगा। दूसरे दिन कथक नृत्य की प्रस्तुतियां कला मंडपम प्रेक्षागृह में होंगी। बिरजू महाराज कथक संस्थान की अध्यक्ष कुमकुम धर ने मंगलवार को संस्थान में आयोजित प्रेसवार्ता में बताया कि बुधवार को होने वाले व्याख्यान में मुख्य वक्ता होंगे प्रसिद्ध नाट्यशास्त्र विशेषज्ञ वाराणसी के डॉ. गौतम चटर्जी। मुख्य अतिथि होंगी भातखंडे विवि की कुलपति प्रो. मांडवी सिंह। पांच फरवरी को कलामंडपम में सुप्रसिद्ध नृत्यांगना व कथक गुरु डॉ. पूर्णिमा पांडेय की मौजूदगी में कथक संस्थान के विद्यार्थियों की प्रस्तुतियां होंगी। पहली प्रस्तुति गायन की, दूसरी प्रस्तुति कथक युगल नृत्य की होगी जिसे असम की मां–बेटी की जोड़ी मरमी मेधी और मेघरंजनी प्रस्तुत करेंगी। तीसरी प्रस्तुति कदम्ब सेंटर फॉर डांस एंड म्युजिक की ओर से की जाएगी। प्रेसवार्ता के दौरान कथक संस्थान की उपाध्यक्ष डॉ. मिथिलेश तिवारी भी मौजूद रहीं।

घर बने मिनी लाइब्रेरी, बच्चों के साथ अभिभावक भी रोज

लखनऊ, (संवाददाता)। घर को बच्चों की पहली पाठशाला बनाने की परंपरा को फिर से जीवंत करने पर जोर देते हुए वक्ताओं ने अभिभावकों से अपील की कि वे घर में लाइब्रेरी जैसा माहौल बनाएं और बच्चों के साथ रोज पढ़ने की आदत विकसित करें। सिटी स्टेशन रोड स्थित राजकीय जुबिली इंटर कॉलेज परिसर में मंगलवार को माध्यमिक शिक्षा विभाग और नेशनल बुक ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित पठन संस्कृत उत्सव के तहत हुए लेखन संवाद में यह बातें सामने आईं। वक्ताओं ने कहा कि अभिभावक प्रतिदिन कम से कम 30 से 45 मिनट बच्चों के साथ पढ़ने में बिताएं। इससे बच्चों में नियमित पठन की आदत बनेगी और डिजिटल स्क्रीन पर निर्भरता भी कम होगी। कार्यक्रम के दौरान पुस्तक प्रदर्शनी, 'बुक नॉट बुक' अभियान से जुड़े आयोजन, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और प्रतियोगिताएं हुईं। लेखन संवाद के पहले सत्र में अपर मुख्य सचिव माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा, वरिष्ठ कथाकार चंद्रशेखर वर्मा और कवि–सांस्कृतिक चिंतक यतींद्र मिश्र ने विचार रखे। राजकीय जुबिली इंटर कॉलेज कक्षा 12वीं के छात्र ऋषभ ने सवाल किया कि क्या पुस्तक मार्गदर्शक के रूप में काम कर सकती है। यशोदा इंटर कॉलेज की 11वीं कक्षा की छात्रा प्रोशी जोशी ने नॉवेल के बारे बारे में पूछा। जब सब कुछ इंटरनेट पर उपलब्ध है तो किताब की जरूरत क्यों। वक्ताओं ने कहा कि पुस्तकें मार्गदर्शक की तरह काम करती हैं और इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के बावजूद सही ज्ञान और समझ के लिए पुस्तकों का पठन जरूरी है।

सीजी सिटी अर्बन वेटलैंड में मना प्रकृति पर्व

लखनऊ, (संवाददाता)। एलडीए के सीजी सिटी अर्बन वेटलैंड में मंगलवार को वेटलैंड डे के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण पर विविध कार्यक्रम हुए। सुबह बर्ड वॉचिंग से कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसमें स्कूली बच्चों और पर्यावरण प्रेमियों ने दूरबीन से पक्षियों का अवलोकन किया। विशेषज्ञों ने पक्षियों की प्रजातियों, उनके व्यवहार और वेटलैंड के पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान की जानकारी दी। मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी ने वेटलैंड की वॉल का अनावरण और नवनिर्मित सोवेनियर शॉप का उद्घाटन किया। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि सोवेनियर शॉप के माध्यम से संरक्षण से जुड़े उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा और गतिविधियों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी। गोमती टास्क फोर्स के साथ स्वच्छता अभियान चलाया गया। पेंटिंग प्रतियोगिता में भाविका यादव ने प्रथम, लक्ष्मी वर्मा ने द्वितीय एवं जरीन ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। एक्सटेम्पोर प्रतियोगिता में पर्यावरण और वेटलैंड संरक्षण पर बच्चों ने विचार प्रस्तुत किए। इसमें प्रीति यादव ने प्रथम, सुहानी कुमारी ने द्वितीय एवं मानसी प्रजापति ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। कार्यक्रम में वेटलैंड संरक्षण, जैव विविधता और शहरी विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर पैनल डिस्कशन हुआ। जिसमें डीएफओ सितांशू पांडेय, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी के पूर्व निदेशक डॉ. असद रहमानी, टीएसए के निदेशक डॉ. शैलेनंद्र सिंह, अंबेडकर विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर राणा प्रताप सिंह, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के एमए खालिद, लखनऊ विश्वविद्यालय की डॉ. अमिता कन्नौजिया व गोमती टास्क फोर्स के मेजर केएस नागी शामिल रहे। विशेषज्ञों ने वेटलैंड की भूमिका, भूजल रिचार्ज, बाढ़ नियंत्रण और तापमान संतुलन पर प्रकाश डालते हुए नागरिकों से प्लास्टिक उपयोग कम करने और जल स्रोतों की रक्षा की अपील की।

अवसानेश्वर मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचे चोर, 8 किलो चांदी समेत 25 लाख की चोरी

लखनऊ, (संवाददाता)। बाराबंकी के हैदरगढ़ स्थित श्री अवसानेश्वर महादेव मंदिर में मंगलवार रात चोरों ने आस्था को निशाना बनाते हुए बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर मंदिर के गर्भगृह तक घुस गए और चांदी के छत्र समेत करीब 8 किलो चांदी व अन्य कीमती पूजा सामग्री लेकर फरार हो गए। चोरी की कुल कीमत करीब 25 लाख रुपये आंकी जा रही है। बुधवार सुबह जब पुजारी मंदिर पहुंचे तो टूटा ताला और बिखरा सामान देखकर चोरी का खुलासा हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल की बारीकी से जांच शुरू की। साथ ही मंदिर परिसर और आसपास के मार्गों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस के मुताबिक, चोरों ने मंदिर के चौनल गेट का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया। प्रत्यक्ष संकेतों से सामने आया है कि एक चोर ने मंकी मास्क पहन रखा था, जिससे पहचान छिपाई जा सके। हैदरगढ़ के कोतवाल अभिमन्यु मल्ल ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जल्द ही खुलासा करने का प्रयास किया जाएगा। चिंताजनक पहलू यह है कि मंदिरों में चोरी की यह कोई पहली घटना नहीं है। बुधवार सुबह ही जानकारी मिली कि बड्डूपुर थाना क्षेत्र के भगौली तीर्थ स्थित मंदिर से भी पूजा सामग्री चोरी कर ली गई। पिछले एक महीने के भीतर जिले के कई मंदिरों में चोरी की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

संक्षिप्त खबरें

कैंसर संस्थान में साइबर नाइफ स्थापित, तीन महीने में मिलेगी सुविधा

लखनऊ, (संवाददाता)। कल्याण सिंह अति विशिष्ट कैंसर संस्थान में मंगलवार को आधुनिक साइबर नाइफ की स्थापना की गई। अगले दो से तीन महीने में इसका लाभ मिलने लगेगा। साइबर नाइफ से बिना चीरा लगाए मस्तिष्क के ट्यूमर का इलाज हो सकेगा। संस्थान के निदेशक प्रो. एमएलबी भट्ट ने बताया कि मशीन की स्थापना से न केवल उत्तर प्रदेश, बल्कि आसपास के राज्यों के कैंसर रोगियों को भी विश्वस्तरीय उपचार संस्थान में ही उपलब्ध हो सकेगा। चिकित्सा अधीक्षक डॉ. वरुण विजय ने बताया कि अभी मशीन की जांच कर उसे मरीजों की उपयोगिता में लाने से पहले रेडिएशन संबंधी मंजूरी की जरूरत पड़ेगी, जिसमें दो से तीन महीने का समय लग सकता है। इस मौके पर रेडिएशन आंकोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉ. शरद सिंह, डॉ. प्रमोद कुमार गुप्ता, डॉ. रूमीता सिंह, संस्थान के वित्त अधिकारी रजनीकांत वर्मा उपस्थित रहे। रोबोटिक आर्म से जुड़े लीनियर एक्सेलेरेटर के जरिये सैकड़ों कोणों से विकिरण दिया जाता है, जिससे अत्यंत सटीक और व्यक्तिगत उपचार संभव होता है।

जलशक्तिमंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने दी सख्त चेतावनी

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश के जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि विभागीय कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही, शिथिलता या अनियमितता को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कार्यों में कोताही पाई गई तो संबंधित अधिकारी एवं कार्मिकों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जो अधिकारी एवं कर्मचारी उत्कृष्ट कार्य करेंगे, उन्हें सम्मानित किया जाएगा, ताकि विभाग में सकारात्मक, उत्तरदायी और परिणामोन्मुखी कार्य संस्कृति को बढ़ावा मिल सके।जलशक्ति मंत्री ने यह निर्देश उदयगंज स्थित सिंचाई विभाग मुख्यालय में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान दिए। शारदा संगठन की समीक्षा बैठक में उन्होंने विभागीय कार्यों की प्रगति की गहन समीक्षा करते हुए स्पष्ट और कड़े निर्देश दिए। बैठक के दौरान विभिन्न निर्माण कार्यों की निर्माण–पूर्व स्थिति और निर्माण पूर्ण होने के पश्चात की स्थिति का तुलनात्मक मूल्यांकन भी किया गया। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी निर्माण कार्य निर्धारित मानकों, गुणवत्ता और समयसीमा के अनुरूप पूर्ण किए जाएँ, जिससे योजनाओं का वास्तविक लाभ किसानों और आम जनता तक सुनिश्चित रूप से पहुँच सके।स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि वे स्वयं शीघ्र ही विभिन्न निर्माण कार्यों का भौतिक निरीक्षण करेंगे, ताकि जमीनी स्तर पर कार्यों की वास्तविक स्थिति का प्रत्यक्ष आकलन किया जा सके। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि किसी भी स्तर पर गड़बड़ी या अनियमितता की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए और पूरी कार्य प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष एवं नियमों के अनुरूप होनी चाहिए।अंत में उन्होंने अधिकारियों से पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी और जवाबदेही के साथ कार्य करने का आह्वान करते हुए कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता सिंचाई परियोजनाओं को समयबद्ध रूप से पूर्ण कर प्रदेश के किसानों को अधिकतम लाभ पहुँचाना है।

तंबाकू, धूम्रपान और शराब छोड़ने से 40 फीसदी कम होता है कैंसर का खतरा

लखनऊ, (संवाददाता)। केजीएमयू में सर्जिकल आंकोलॉजी विभाग के प्रो. समीर गुप्ता के अनुसार तंबाकू, धूम्रपान और शराब छोड़कर कैंसर का खतरा 40 फीसदी तक कम किया जा सकता है। विश्व कैंसर दिवस की पूर्व संध्या पर पल्मोनरी मेडिसिन विभाग में हुई प्रेसवार्ता में प्रो. समीर गुप्ता ने बताया कि कैंसर में शरीर की सामान्य कोशिकाओं के एक समूह में होने वाले बदलाव के कारण अनियंत्रित और असामान्य वृद्धि होने लगती है। इससे ट्यूमर (गांठ) बनती है। समय पर उपचार न होने पर ट्यूमर आसपास के स्वस्थ ऊतकों में फैल सकते हैं। इस मौके पर पल्मोनरी एवं क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष प्रो. वेद प्रकाश, प्रो. शैलेंद्र यादव और डॉ. सीमा गुप्ता मौजूद रहे। इस मौके पर पद्मश्री सम्मान के लिए प्रो. राजेंद्र प्रसाद के नाम की घोषणा होने पर उनको सम्मानित किया गया। सभी ने उन्हें लखनऊ का गौरव बढ़ाने के लिए बधाई दी। शराब, मोटापा, खराब आहार, शारीरिक निष्क्रियता, तंबाकू सेवन, एक्स–रे, गामा किरणें, पराबैंगनी किरणें, कार्यस्थल जोखिम जैसे एस्बेस्टस जैसे रसायन, संक्रमण, आनुवंशिक कारण, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली। असामान्य गांठ या सूजन, लगातार खांसी, सांस फूलना या निगलने में कठिनाई, मल त्याग की आदतों में परिवर्तन, बिना कारण रक्तस्राव, अचानक वजन घटना, अत्यधिक थकान, लगातार या बार–बार होने वाला दर्द, शरीर में मौजूद तिल में परिवर्तन, स्तन में असामान्य परिवर्तन, भूख में कमी, ऐसा घाव जो ठीक न हो। कैंसर का पता चलने पर हमने डरने के बजाय इलाज पर ध्यान दिया। नियमित इलाज से आज हम कैंसर से मुक्त हो चुके हैं। शहीद पथ स्थित निजी अस्पताल में मंगलवार को कैंसर सर्वाइवर्स के लिए हुए कार्यक्रम में ठीक हो चुके लोगों ने यह बात कही। इससे पहले इन सर्वाइवर्स ने यूपी टूरिज्म की डबल डेकर बस पर सवार होकर 1090 चौराहे से लेकर विधानसभा, रेजिडेंसी पार्क से हेतु हुए यूपी दर्शन पार्क का भ्रमण किया। कार्यक्रम के दौरान डॉ. राकेश कपूर ने कहा कि कैंसर अब लाइलाज बीमारी नहीं है। समय पर पहचान और सही इलाज मरीज के जीवन को नई दिशा देता है।

विश्व कैंसर दिवस से पूर्व यूपीएसटीडीसी की संवेदनशील पहल

लखनऊ, (संवाददाता)। विश्व कैंसर दिवस से पूर्व मानवीय संवेदना और सामाजिक सरोकार की मिसाल पेश करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम (यूपीएसटीडीसी) ने राजधानी लखनऊ में एक भावनात्मक और प्रेरणादायी पहल की। उपचार के कठिन दौर से गुजर रहे एक अस्पताल के 30 कैंसर मरीजों को शहर की विरासत और खूबसूरती से रूबरू कराने के उद्देश्य से लखनऊ दर्शन डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस के माध्यम से विशेष शहर भ्रमण कराया गया। यह विशेष टूर 03 फरवरी को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक आयोजित किया गया, जो लखनऊ दर्शन की नियमित सुबह–शाम सेवाओं से अलग था।विभिन्न आयु वर्ग के मरीजों, डॉक्टरों और सहयोगी मेडिकल स्टाफ की मौजूदगी में आयोजित इस विशेष भ्रमण का उद्देश्य इलाज के दबाव से कुछ पल की राहत देकर मरीजों को शहर की खूबसूरती और जीवन के सकारात्मक रंगों से दोबारा जोड़ना था। पूरी यात्रा को मरीजों की सुविधा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सावधानीपूर्वक संचालित किया गया। भ्रमण के दौरान हर यात्री के चेहरे पर सुकून, उम्मीद और मुस्कान की झलक साफ दिखाई दी।पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि लखनऊ दर्शन बस के माध्यम से किया गया यह विशेष आयोजन केवल पर्यटन गतिविधि नहीं, बल्कि मानवीय संवेदना और सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ा एक सार्थक प्रयास है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से अस्पतालों में उपचाररत कैंसर मरीजों को खुले वातावरण में लाकर शहर की सांस्कृतिक विरासत से जोड़ना, उनका मनोबल बढ़ाना और उनके चेहरों पर मुस्कान लाना इस पहल का मूल उद्देश्य रहा। यह आयोजन इस बात का संदेश देता है कि पर्यटन केवल घूमने–फिरने तक सीमित नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाने का भी एक प्रभावी माध्यम है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पर्यटन आगे भी ऐसी पहलों के माध्यम से पर्यटन को अधिक संवेदनशील और समावेशी बनाने के लिए कार्य करता रहेगा।कई मरीजों के लिए यह भ्रमण अस्पताल की दिनचर्या से बाहर निकलकर सामान्य जीवन को महसूस करने का अवसर बना। शहर की हलचल, ऐतिहासिक इमारतों और खुले वातावरण में एक साथ समय बिताने से मरीजों में आत्मीयता और मानसिक सुकून देखने को मिला।

गन्ने से बेहतर गुड़ बनाने की नई तकनीक सीखेंगे किसान और उद्यमी

लखनऊ, (संवाददाता)। गन्ने से गुड़ उत्पादन को अधिक लाभकारी और गुणवत्ता आधारित बनाने की दिशा में लखनऊ में विशेष तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। भाकृअनुप–भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान में आयोजित पांच दिवसीय प्रशिक्षण में किसानों और उद्यमियों को आधुनिक उत्पादन, प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन की तकनीकों का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। छह फरवरी तक चलने वाले कार्यक्रम का आयोजन उद्यमिता एवं कौशल विकास योजना के अंतर्गत किया गया है। प्रशिक्षण में पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से 20 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। प्रशिक्षण के दौरान यह भी बताया जा रहा है कि गुड़ निर्माण के लिए सभी गन्ना किस्में उपयुक्त नहीं होतीं, इसलिए सही किस्म का चयन उत्पादन और गुणवत्ता दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही गन्ना उत्पादन तकनीक और श्रम बचाने के लिए संस्थान के विकसित उपकरणों के उपयोग का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कार्यक्रम का शुभारंभ संस्थान के निदेशक डॉ. दिनेश सिंह ने किया। इस मौके पर कृषि अभियंत्रण विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. एमके सिंह, प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रशिक्षण निदेशक डॉ. दिलीप कुमार, प्रशिक्षण समन्वयक राजीव रंजन राय, मिथिलेश तिवारी सहित डॉ. श्यामनाथ, डॉ. हिमांशु, शेखर पांडेय, डॉ. प्रियंका, डॉ. विनिका सिंह, रानी मिश्रा और ज्योति सिंह मौजूद रहे।

बलरामपुर अस्पताल बनेगा मेडिकल कॉलेज, डिप्टी सीएम ने दिए प्रस्ताव बनाने के निर्देश

लखनऊ, (संवाददाता)। बलरामपुर अस्पताल जल्द ही मेडिकल कॉलेज के रूप में नई पहचान बनाएगा। मंगलवार को अस्पताल के 157वें स्थापना दिवस समारोह में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इसकी घोषणा की। कहा कि यदि अस्पताल प्रशासन प्रस्ताव बनाकर देता है, तो सरकार सभी जरूरी संसाधन मुहैया कराकर इसे मेडिकल कॉलेज का दर्जा दिलाएंगे। समारोह में डिप्टी सीएम ने अस्पताल में नई डायलिसिस यूनिट, सोलर पैनल और वार्ड 11 में नवीन लिफ्ट का लोकार्पण किया। अस्पताल प्रशासन को निर्देशित किया कि आईसीयू में बेड बढ़ाएं और डायलिसिस की वेटिंग पूरी तरह खत्म करें। अस्पताल प्रशासन की ओर से उपलब्ध कराई गई बुकलेट में पांच दिन की वेटिंग का जिक्र होने पर उन्होंने ये निर्देश दिए। हालांकि, सीएमएस डॉ. हिमांशु चतुर्वेदी ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में अस्पताल में डायलिसिस के लिए मरीजों को अब इंतजार नहीं करना पड़ रहा है। कार्यक्रम में राज्यमंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह, निदेशक डॉ. कविता आर्या, सीएमओ डॉ. एनबी सिंह और स्वास्थ्य विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। डिप्टी सीएम ने निर्देश दिए कि अस्पताल से कोई भी मरीज बिना इलाज वापस नहीं जाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने गेट पर ही दो विशेष कर्मचारियों की तैनाती करने को कहा, जो मरीजों को भर्ती कराने और बेड दिलाने में सीधे मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि यदि बेड खाली न हो, तो अतिरिक्त बेड की व्यवस्था करें, लेकिन इलाज सुनिश्चित हो। डिप्टी सीएम ने अस्पताल के स्वर्णिम इतिहास की सराहना करते हुए कहा कि यह संस्थान डेढ़ सदी से अधिक समय से मरीजों की सेवा कर रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व मुख्यमंत्री रामप्रकाश गुप्ता समेत कई हस्तियों ने यहां इलाज कराया है। राज्यमंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने कहा कि शहर के बड़े चिकित्सा संस्थानों केजीएमयू, लोहिया, पीजीआई के बीच बलरामपुर अस्पताल ने खुद को स्थापित कर रखा है। इतने अधिक बेड प्रदेश के किसी भी सरकारी अस्पताल में नहीं हैं। तीनों बड़े संस्थानों के बराबर बलरामपुर अस्पताल की ओपीडी चल रही है। उन्होंने बताया, मैं अपने घरवालों से कहूंगा कि यदि मैं बीमार हूं तो लोहिया और बलरामपुर ही ले जाएं। मंत्री बनने के बाद दो बार बीमार पड़ा। एक बार बलरामपुर और लोहिया गया और स्वस्थ होकर लौटा।

फिटनेस, फैशन और मस्ती का अनोखा संगम बना 'द एथलीजर फेस्ट'

लखनऊ आर एल पाण्डेय। फीनिक्स पलासियो ने अपने भव्य एट्रियम को फिटनेस और एथलीजर के रंग में रंग दिया है। यहां 'द एथलीजर फेस्ट' की शुरुआत के साथ ही फैशन, फिटनेस और मस्ती का ऐसा माहौल बन गया है, जो शहर के युवाओं और फिटनेस प्रेमियों को खास तौर पर आकर्षित कर रहा है। यह फेस्ट 29 जनवरी से शुरू होकर 22 फरवरी तक चलेगा और तीन लगातार वीकेंड तक लोगों को एक्शन और एनर्जी से भरपूर अनुभव देगा। फेस्ट को इस तरह तैयार किया गया है कि यहां शॉपिंग के साथ–साथ एक्टिव लाइफस्टाइल को करीब से महसूस किया जा सके। फीनिक्स पलासियो के स्पोर्ट्स और फिटनेस ब्रांड्स को आकर्षक इंस्टॉलेशंस, प्रजेंटेशन और लाइव एक्टिविटीज के जरिये पेश किया गया है। यहां साइक्लिंग चौलेंज, रिफ्लेक्स परखने वाले गेम्स, टायर फ्लिप, जुम्बा डांस, पुशअप्स और स्क्वाट चौलेंज, रोप और स्किपिंग एक्टिविटी जैसी कई फिटनेस गतिविधियां लोगों को खुद को आजमाने का मौका दे रही हैं। इसके साथ ही सोशल मीडिया के लिए खास तौर पर तैयार किए गए एक्सपीरियंस जोन भी युवाओं के बीच खासे लोकप्रिय हो रहे हैं। फेस्ट के दौरान मॉल में कई रोमांचक गेम्स और एंड्योरेंस चौलेंज भी रखे गए हैं, जिनमें हिस्सा लेकर विजिटर्स आकर्षक इनाम जीत सकते हैं। इस पहल का मकसद सिर्फ खरीदारी तक सीमित न रहकर लोगों को एक ऐसा लाइफस्टाइल अनुभव देना है, जिसमें सेहत, स्टाइल और एंटरटेनमेंट एक साथ जुड़ते हैं। इस मौके पर संजीव सरीन, रीटेल डायरेक्टर (नॉर्थ), फीनिक्स मिल्स ने कहा, "फीनिक्स पलासियो में हमारा प्रयास हमेशा यही रहता है कि हम रिटेल से आगे बढ़कर यादगार अनुभव दें। 'द एथलीजर फेस्ट' लखनऊ की उस पीढ़ी का उत्सव है, जो फिटनेस को लेकर जागरूक है और स्टाइल में भी आगे रहना चाहती है। इनोवेशन, इंटरऐक्शन और मनोरंजन के जरिये हम ऐसा मंच बना रहे हैं, जहां फिटनेस और फैशन एक साथ लोगों को प्रेरित करते हैं।" उच्च ऊर्जा से भरपूर सेटअप, इंटरैक्टिव जोन्स और वीकेंड–लॉन्ग एक्टिविटीज के साथ 'द एथलीजर फेस्ट' यह दिखाता है कि फीनिक्स पलासियो अब सिर्फ शॉपिंग मॉल नहीं, बल्कि एक ऐसा लाइफस्टाइल डेस्टिनेशन बन चुका है, जहां लोग बार–बार लौटना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं और कुछ नया महसूस करना चाहते हैं।

साइबर ठगी का शिकार हुआ डीएससीएल का एक कर्मचारी, 1.58 लाख उड़े'

'रिपोर्ट–जनार्दन श्रीवास्तव'

'पाली–(हरदोई)' कस्बा पाली में साइबर अपराधियों ने बुधवार को डीएससीएल शुगर मिल में कार्यरत एक कर्मचारी को अपना शिकार बना लिया। चीनी मिल कर्मचारी कृष्णा प्रसाद राय के अलग–अलग दो बैंक खातों से साइबर ठगों ने 1.58 लाख रुपये उड़ा दिये। घटना 04 फरवरी की है। जानकारी के मुताबिक कृष्णा प्रसाद राय के पास बुधवार में दोपहर को उनके किसी मित्र के नाम से साइबर ठग का फोन आया।फोन पर ठग मित्र ने बताया कि मेरी माता जी लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं। तकनीकी समस्या के कारण मेरे मोबाइल से लेनदेन हो नहीं पा रहा है। मुझे माता जी के इलाज के लिए अस्पताल में तुरंत पैसा जमा करना है। मैं रुपये आपके खाते में भेज रहा हूँ और आप मेरे द्वारा भेजे गए रुपयों को उक्त मोबाइल नंबर पर सेंड कर दें। और उसने अपना मोबाइल नंबर सेंड कर दिया। बातचीत के दौरान साइबर ठग ने लगभग 1.50 लाख रुपयों के फर्जी मैसेज कृष्णा प्रसाद राय के मोबाइल नंबर पर भेज दिये। कृष्णा प्रसाद राय ने समझा कि मेरे मित्र ने मेरे खाते में रुपये भेज दिये हैं। साइबर ठग द्वारा भेजे गए रुपयों के मैसेज भी कृष्णा प्रसाद राय के मोबाइल नंबर पर आ गए। कृष्णा प्रसाद राय ने अपने मोबाइल पर ठग मित्र द्वारा भेजे हुए रुपयों के मैसेज को देखकर अपने मोबाइल से चार बार में रुपये ठग मित्र के खाते में ट्रांसफर कर दिये। कृष्णा प्रसाद राय ने बताया कि मैंने अपने मोबाइल पर खाते में क्रेडिट का मैसेज तो देखा लेकिन अपना बैलेंस चेक नहीं किया। लेकिन जब बैलेंस चेक किया तब तक काफी देर हो चुकी थी।उनका कहना है कि बस यही सबसे बड़ी भूल हुई। दो खातों से 1.58 लाख रुपये की ठगी से पूरा परिवार काफी दुःखी है। साइबर ठगी से पीड़ित परिवार द्वारा सूचना पाली थाना पुलिस को दे दी गई है।

संक्षिप्त खबरें

शिवांगी दूबे ने जे आर एफ परीक्षा उत्तीर्ण कर बढाया क्षेत्र का मान

(राजन तिवारी सिटी रिपोर्टर अयोध्या)

अयोध्या।श्रीराम बल्लभा इण्टर कालेज डयोढी के शिक्षक व सोहावल तहसील के अरथर गाँव निवासी डाक्टर राकेश दूबे की पुत्री शिवांगी द्विवेदी ने विश्व विद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा –2026 जे आर एफ परीक्षा उत्तीर्ण कर क्षेत्र का मान बढाया है। शिवांगी द्विवेदी की प्रारंभिक शिक्षा ग्रामीण परिवेश में स्नातक एवं परास्नातक की पढ़ाई लखनऊ विश्व विद्यालय से पूरी की। बिटिया की सफलता पर परिजनों एवं क्षेत्रवासियों ने अपनी शुभकामनाएं दी है। बिटिया की सफलता पर उसके पैतृक गांव में खुशी का माहौल है।

कृषि विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या। जनपद अयोध्या के कृषि भवन सभागार मे जिला स्तरीय अधिकारी एवं ब्लाक स्तर अधिकारियों कर्मचारियों के लिए नैनो उर्वरक उपयोग एवं लाभ आधारित एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि संयुक्त कृषि निदेशक डॉ ए0के0 मिश्रा, अन्य विशिष्ट अतिथिद्वय उप कृषि निदेशक, डॉ पी0के0कन्नौजिया , जिला कृषि अधिकारी श्री ओ0पी0 मिश्रा सहित अपर जिला कृषि अधिकारी श्री राहुल कुमार मिश्र ,वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप ए दीपांकर सिंह बादल उपस्थित रहे।कार्यक्रम में जनपद के समस्त एडीओ कृषि , एटीएम , बीटीएम ने प्रतिभाग किया।इफको राज्य कार्यालय लखनऊ से पधारे डॉ आर के नायक, उप महाप्रबंधक कृषि सेवाएं ने सभी प्रतिभागी अधिकारी कर्मचारियों को नैनो उर्वरकों के बारे में तकनीक जानकारी एवं उर्वरकों के लाभ व रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुन प्रयोग से मृदा स्वास्थ्य पर होने वाले हानिकारक दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी दी एवं रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम करने एवं जैविक उर्वरक वह नैनो उर्वरक के समेकित प्रयोग करने की सलाह दी नैनो यूरिया नैनो डीएपी नैनो जिंक नैनो कॉपर की प्रयोग करने की विधि को कर्मचारियों को विस्तार पूर्वक समझाया।जिला कृषि अधिकारी ओ0पी0 मिश्रा द्वारा पीएम प्रणाम योजना अंतर्गत रासायनिक उर्वरकों के हानिकारक प्रभाव एवं अधिक उपयोग के बारे में व वैकल्पिक उर्वरकों के रूप में नैनो उर्वरकों के राजकीय कृषि फार्म पर प्रदर्शन व परीक्षण कर पुष्ट जानकारी को किसानों के बीच साझा करते हुए किसानों को समझाने पर बल दिया।उप कृषि निदेशक, डॉ पी0के0कन्नौजिया ने नैनो उर्वरक व अन्य वैकल्पिक उर्वरकों के सकारात्मक प्रभाव के बारे में सभी को जानकारी दी।मुख्य अतिथि संयुक्त कृषि निदेशक डॉ ए0के0 मिश्रा ने सभी प्रतिभागियों से आह्वान किया कि सभी लोग अधिक से अधिक फील्ड मेंप्रदर्शन कर उसके प्रभावों सीखकर ही नई तकनीकि को किसानों को बताए।साथी सभी बीज केंद्रों व राजकीय कृषि फार्मों पर इफको से सभी उत्पादों का डिस्प्ले कर प्रचार प्रसार के निर्देश दिए इफको उप क्षेत्र प्रबंधक विवेक त्रिवेदी द्वारा कार्यक्रम का संचालन किया गया। इस अवसर पर कृषि विभाग से 75 कर्मचारी ध्‍ प्रसार अधिकारी सहित इफको से एस एफ ए सतीश कुमार व निर्मल कुमार इफको एमसी से उपेंद्र वर्मा, भी उपस्थित रहे।

बिग सेम सीमेंट के सेल्स हेड यूपी ईस्ट एंड सेंट्रल राजीव मेहता ने परिजनों संग किया रामलला का किया दर्शन पूजन

अयोध्या।गुरुवार को बिग सेम सीमेंट के सेल्स हेड यूपी ईस्ट एंड सेंट्रल राजीव मेहता ने अपने परिजनों के साथ रामलला का दर्शन पूजन किया।इस मौके पर उन्होंने बताया कि केंद्र में मोदी सरकार तथा राज्य में योगी सरकार के कारण आज अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है।इस मौके पर उन्होंने कहा कि राम मंदिर के निर्माण के होने से सिर्फ अयोध्या ही नहीं आसपास के जिलों में भी इसके विकास को देखा जा सकता है।वही अयोध्या धाम में भी अब बाहर से भी नामी गिरामी कंपनियां,होटल सहित अन्य प्रमुख प्रतिष्ठानों को भी स्थापित कर रही हैं।जिससे कि यहां के स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिल रहा है।उन्होंने बताया कि हां इतना जरूर है राम मंदिर में श्रद्धालुओं का आकर्षण बढ़ाने के लिए केंद्र व राज्य सरकार को यातायात की सुविधा में बढ़ोतरी करनी होगी जैसे कि मथुरा,बनारस की तरह जिस तरह सभी शहरों से ट्रेनों की कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी है उसी तरीके से अयोध्या से गुजरने वाले ट्रेनों की भी हो। वही विभिन्न शहरों के लिए अयोध्या से फ्लाइट की भी व्यवस्था हो।बताते चलें उन्होंने अपनी पत्नी बेटी तथा अन्य परिजनों के साथ राम मंदिर का दर्शन पूजन करने के बाद हनुमानगढ़ी, कनक भवन,अन्य प्रमुख मंदिरों पर जाकर दर्शन पूजन किया।

फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, शिक्षकों एवं शोधकर्ताओं के लिए अत्यंत ज्ञानवर्धक एवं लाभकारी सिद्ध होगा

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। श्री शारदा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, लखनऊ द्वारा "भारतीय ज्ञान प्रणाली एवं सार्वजनिक स्वास्थ्यरू प्राचीन जड़ें, आधुनिक प्रभाव" विषय पर एक सप्ताह–व्यापी फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम (थ्क्च्) का सफल आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारतीय ज्ञान परंपरा में निहित सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित प्राचीन अवधारणाओं को समझना, उनके आधुनिक संदर्भों का विश्लेषण करना तथा अकादमिक एवं शोध कार्यों में उनके व्यावहारिक अनुप्रयोग को प्रोत्साहित करना रहा। कार्यक्रम में देश के विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से जुड़े शिक्षकों एवं शोधार्थियों ने सक्रिय सहभागिता की। कार्यक्रम के अंतर्गत त्रिपुरा विश्वविद्यालय (केन्द्रीय विश्वविद्यालय) के प्राणी विज्ञान विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ को रिसोर्स पर्सन एवं मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया। उनके व्याख्यानों के माध्यम से प्रतिभागियों को भारतीय ज्ञान प्रणाली और सार्वजनिक स्वास्थ्य के पारस्परिक संबंधों पर गहन एवं व्यावहारिक दृष्टिकोण प्राप्त हुआ। एफडीपी के दौरान भारतीय ज्ञान प्रणाली, आयुष, पारंपरिक स्वास्थ्य पद्धतियाँ, पर्यावरणीय स्वास्थ्य तथा समकालीन सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विशेषज्ञ व्याख्यान एवं संवाद सत्र आयोजित किए गए। कार्यक्रम में डॉ. लक्ष्मी शंकर अवस्थी, डीन (एकेडमिक्स), लखनऊ पब्लिक कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज तथा डॉ. आनंद कुमार राय, एसोसिएट प्रोफेसर, कंप्यूटर साइंस विभाग, लखनऊ पब्लिक कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, लखनऊ ने भी विशिष्ट वक्ता के रूप में सहभागिता की। कार्यक्रम के आयोजक डॉ. विवेक मिश्रा, डीन (एकेडमिक्स), श्री शारदा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, लखनऊ ने विश्वास व्यक्त किया कि यह फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम शिक्षकों एवं शोधकर्ताओं के लिए अत्यंत ज्ञानवर्धक एवं लाभकारी सिद्ध होगा तथा भारतीय ज्ञान परंपरा को समकालीन शिक्षा एवं शोध से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

संक्षिप्त खबरें

सील दुकान में युवती के कैद होने का आरोप नगर आयुक्त ने बताया गलत

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या। नगर निगम ने मोहल्ला फतेहगंज में गृह एवं जलकर के बकाएदार स्वर्गीय बेचन राम की दुकान (भवन संख्या 06ध्20ध्25) के सील करने के दौरान युवती के कैद होने के आरोप को बेबुनियाद बताया है और आशंका जताई है कि नगर निगम को बदनाम करने की साजिश के तहत युवती को बाद में पीछे के रास्ते से दुकान में ले जाया गया था।नगर आयुक्त जयेंद्र कुमार ने सील दुकान में युवती के कैद होने के आरोप पर स्पष्ट किया कि स्वर्गीय बेचन राम पर 90,800 गृह एवं जलकर के रूप में बकाया था, जिसकी वसूली के लिए 29 जून 2025 को बकाया बिल भेजा गया। बिल भुगतान न होने पर 17 नवंबर 2025 को डिमांड नोटिस जारी की गई, जो उन्हें 25 नवंबर 2025 को तामील कराया गया। इसके बाद क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक देवीप्रसाद द्वारा कई बार टैक्स जमा करने के लिए व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया गया। बकाया न जमा होने पर कुर्की की कार्रवाई के लिए 17 जनवरी 2026 को समाचार पत्र में सार्वजनिक नोटिस प्रकाशित कराई गई। इसके बाद भी बकाया न जमा करने पर चार फरवरी 2026 को कुर्की के लिए नगर निगम की टीम क्षेत्रीय पुलिस बल एवं प्रवर्तन दस्ता के साथ लगभग1रू30 बजे दोपहर नियत स्थल पर पहुंची। उन्होंने बताया कि दूकान सील करने की कार्रवाई के दौरान फतेहगंज चौकी प्रभारी दो महिला पुलिस कर्मी के साथ मौजूद थे।उन्होंने दुकान के भीतर की जांच भी की थी। इस दौरान बेचन राम की वारिशों में से दो लोगों संतोष कुमार एवं बैजनाथ ने अपना–अपना बकाया धनराशि 30–30 हजार रुपये जमा कर दिए और उन्हें इसकी रसीद भी दे दी गई, किंतु तीसरे वारिस रिंकू गुप्ता ने बकाया कर देने से इनकार करते हुए विवाद किया और दुकान सील करने को कहा। नगर आयुक्त ने बताया कि दुकान सील करने की कार्रवाई पूरी तरह से जांचोपरांत की गई। नगर निगम के पास दुकान सील करने की कार्रवाई के दौरान का वीडियो उपलब्ध है, जिसमें युवती को बाहर करते साफ देखा जा सकता है। नगर निगम की टीम के लौटने के छह घंटे बाद खड्यंत्र के तहत जानबूझकर लड़की के कैद होने का तथ्य संज्ञान में लाया गया। नगर निगम कोतवाली पुलिस को जांच के लिए पत्र लिखा है। पत्र में आशंका जताई गई है कि पीछे के रास्ते से युवती को दोबारा मकान में ले जाया गया था।

सैमसंग इनोवेशन कैंपस ने कर्नाटक में 2,000 युवाओं को किया प्रमाणित, भविष्य के लिए तैयार तकनीकी प्रतिभा को मिला नया बल

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

दिल्ली। भारत के सबसे बड़े उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड सैमसंग ने अपने प्रमुख कौशल विकास कार्यक्रम सैमसंग इनोवेशन कैंपस के तहत कर्नाटक में 2,000 छात्रों के सफल प्रमाणन की घोषणा की। यह पहल राज्य में भविष्य के लिए तैयार टेक्नोलॉजी टैलेंट तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 1,100 छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा 900 छात्रों को कोडिंग और प्रोग्रामिंग में प्रमाणित किया गया। प्रशिक्षण के साथ–साथ छात्रों को सॉफ्ट स्किल्स और रोजगार क्षमता बढ़ाने हेतु मार्गदर्शन भी प्रदान किया गया। प्रमाणन समारोह कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बेंगलुरु में आयोजित हुआ, जिसमें कर्नाटक सरकार के वरिष्ठ मंत्री एवं सैमसंग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। सैमसंग साउथवेस्ट एशिया के कॉर्पोरेट वाइस प्रेसिडेंट श्री एस.पी. चुन ने कहा, "सैमसंग इनोवेशन कैंपस युवाओं को भविष्य की तकनीकों में प्रशिक्षित कर शिक्षा और रोजगार के बीच की दूरी को कम कर रहा है।" कर्नाटक सरकार के श्रम मंत्री श्री संतोष एस. लाड ने इस पहल को युवाओं को फ्यूचर–रेडी बनाने की दिशा में अहम बताया। सैमसंग इनोवेशन कैंपस वर्तमान में देश के 10 राज्यों में संचालित हो रहा है और समावेशी डिजिटल स्किलिंग को बढ़ावा दे रहा है।

प्रवीण कुमार बने अपर पुलिस महानिदेशक जोन लखनऊ, सोमेन वर्मा बने डीआईजी रेंज अयोध्या

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या। यूपी मे पिछले दिनों आईपीएस के प्रमोशन के बाद से तबादला लिस्ट का इंतजार किया जा रहा था। लिस्ट तैयार थी।मुख्यमंत्री के साइन होने बाकी थे।आज देर रात आखिर तबादले हो गए।प्रमोशन के बाद अयोध्या के आईजी प्रवीण कुमार जब एडीजी बने तो उनका हटना तय था।अब प्रवीण कुमार एडीजी लखनऊ जोन हो गए हैं।एडीजी लखनऊ जोन बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट मानी जाती है।विक्रमादित्य मार्ग पर दफ्तर है।सपा मुख्यालय के बगल में प्रवीण कुमार लखनऊ के एसएसपी भी रहे हैं।बेहद सुलझे हुए आईपीएस अफसर हैं.. बहुत संवेदनशील हैं।कवि हृदय हैं।कविताएं लिखते हैं।किताबें भी छप चुकी हैं।सेंगर साहब के आने के बाद से लखनऊ बहुत कमजोर हो गया है.. सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक की है.. लॉ एंड आर्डर में भी कुछ संभल नहीं रहा है.. जाहिर है, प्रवीण जी आये हैं तो वो ही संभालेंगे.. प्रवीण जी अब यहां अपने जलवे दिखाएंगे।लखनऊ जोन के एडीजी सुजीत पांडे प्रमोशन की पिछली लिस्ट में एडीजी से डीजी बन गए हैं तो उनको जाना ही था।आज की इस लिस्ट में उनको अग्निशमन एवं आपात सेवाओं का डीजी बनाया गया है।आईपीएस तो बहुत हैं लेकिन कुछ प्रमुख के नाम का जिक्र यहां पर जरूरी है।मसलन गोरखपुर के एसएसपी राजकरन नैय्यर.. मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र के हैं.. प्रमोशन हुआ, डीआईजी बने तो गाजियाबाद भेजे गए हैं, अपर पुलिस आयुक्त बनाकर. . मुझे ऐसा लगता है सीएम साहब की कोई नाराजगी थी, शायद इसीलिए बरफ में लगा दिए गए.. आईपीएस सोमेन बर्मा.. मिर्जापुर में दुर्गा पूजा पंडाल में इनको आपने धुनुची नृत्य करते हुए देखा होगा.. प्रमोशन हुआ. . डीआईजी बने तो अब अयोध्या परिक्षेत्र की जिम्मेदारी मिली है.. यानि डीआईजी रेंज अयोध्य।धुनुची नृत्य ने इज्जत बचा ली.. सही जगह आ गए.. हालांकि अब वहां सार्वजनिक मंच पर ज्यादा ष्धुआंष नहीं उड़ा पाएंगे। अब ये जानिए, किसकी–किसकी रंगबाजी चली गई..आईपीएस आशीष तिवारी, सहारनपुर के एसएसपी थे.. प्रमोशन के बाद अब तकनीकी सेवाओं के डीआईजी होंगे।दिखाइए तकनीकी कौशल साहब जी.. नहीं आता है तो सीखिए!!आईपीएस अभिषेक यादव, पीलीभीत के एसपी थे.. मुख्यमंत्री जी के साथ बहुत फोटो खिंचाई लेकिन काम नहीं आई.. प्रमोशन हुआ, डीआईजी बने.. जिला छिन गया।अब एटीएस में डीआईजी होंगे.. यानि आकाओं के इशारे पर काम करेंगे।आईपीएस विपिन टाडा.. मेरठ के एसएसपी थे, अब कानपुर में जेसीपी होंगे.. संदेश साफ है.. कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे.. आईपीएस आशीष तिवारी सहारनपुर के एसपी थे, डीआईजी हो गए.. अब तकनीकी सेवाएं देखेंगे.. मतलब कंप्यूटर, इंटरनेट, साइबर.. इससे आगे जानकार निकले तो डीपफेक, डार्क नेट आदि आदि..आईपीएस संकल्प शर्मा.. खीरी के एसपी थे, अब कानपुर कमिश्नरेट में जेसीपी होंगे।अब जानिए किसकी लॉटरी लगी. . आईपीएस ख्याति गर्ग.. मुरादाबाद पीएसी में सेनानायक थीं.. उनको खीरी का एसपी बनाया गया है.. बहुत महत्वपूर्ण जिला है.. जैसे उनके तेवर हैं, देखकर लगता है संभाल लेंगी.. बाकी लखनऊ में प्रवीण जी बैठे ही हैं.. आईपीएस चारू निगम.. हेकड़ी वाली आईपीएस हैं.. किसी को सेंटती नहीं.. विधायक–मंत्री उनके दफ्तर में घुसने से पहले तीन बार सोचते हैं.. कई जिलों में जबरदस्त रंगबाजी दिखाई.. सरकार को हजम नहीं हुआ तो गाजियाबाद 47वीं वाहिनी पीएसी का सेनानायक बनाकर बैठा दिया.. अब सुल्तानपुर की एसपी बनाई गई हैं.. मैडम की रंगबाजी यहां भी बदस्तूर रहेगी, मुझे ऐसा विश्वास है. .आईपीएस अविनाश पांडेय, एसएसएफ 01वीं वाहिनी के सेनानायक को एसएसपी मेरठ बनाया गया है.. पांडे जी को बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है.. आईपीएस रवि कुमार, 11वीं वाहिनी पीएसी सीतापुर के सेनानायक को रायबरेली का एसपी बनाया गया है. रायबरेली सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण जिला है.. आईपीएस सुकीर्ति माधव, इंटेलिजेंस आगरा के एसपी को पीलीभीत का एसपी बनाया गया है.. वाराणसी कमिश्नरेट में तैनात आईपीएस

60 फीट ऊंचाई पर पेड़ से लटका मिला युवक का शव, पांच घंटे लगे उतारने में

लखनऊ, (संवाददाता)। चारबाग की सेकंड एंट्री के पास बुधवार दोपहर एक युवक का शव बरगद के पेड़ से मफलर के सहारे 60 फीट ऊंचाई पर लटका मिला। पांच घंटे की मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने हाइड्रोलिक मशीन की मदद से युवक के शव को नीचे उतारा। फिलहाल युवक की पहचान नहीं हो सकी है। एसपी हजरतगंज विकास जायसवाल ने बताया कि करीब 12 बजे नाका पुलिस को स्टेशन के पीछे पेड़ से युवक के लटके होने की सूचना मिली थी। पुलिस ने शव उतारने का प्रयास किया, लेकिन ऊंचाई अधिक होने के कारण सफलता नहीं मिली। इसके बाद फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ को बुलाया गया। सामान्य सीढ़ी से ऊंचाई तक न पहुंच पाने के कारण हाइड्रोलिक मशीन मंगवाई गई। घंटों की जद्दोजहद के बाद शव को पेड़ से नीचे उतारा जा सका। पुलिस ने आसपास के लोगों से शिनाख्त कराने का प्रयास किया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। इसके बाद शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। एसीपी का कहना है कि युवक पेड़ के ऊपर कैसे पहुंचा, इसकी जांच की जा रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। युवक की उम्र लगभग 35 वर्ष बताई जा रही है। उसने काले रंग की पैंट और जैकेट पहनी हुई थी। हाइड्रोलिक मशीन के संचालक ओंकारनाथ राव ने बताया कि दोपहर करीब दो बजे उन्हें सूचना मिली थी। मौके पर पहुंचने पर गाड़ी लगाने में भी काफी दिक्कतें आईं। पेड़ की कुछ डालियों को काटना पड़ा, जिसके बाद पांच लोगों की टीम विजय पाल सिंह, राजीव कुमार यादव, मनोज कुमार पांडे और ललित कुमार पांडेय ने मिलकर हाइड्रोलिक मशीन की सहायता से शव को नीचे उतारा।

जिले में चार स्थानों पर बनेगा स्थायी हेलिपेड

भदोही, (संवाददाता)। जिले के हर ब्लॉक में एक–एक स्थायी हेलिपैड बनाया जाएगा, ताकि आपातकालीन स्थितियों व वीआईपी मूवमेंट में उनका उपयोग किया जा सके। शासन से निर्देश के बाद जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। डीएम शैलेष कुमार के निर्देश पर चार ब्लॉकों में जमीन चिह्नित कर ली गई है। इसमें सीतामढ़ी समेत चार जगह चयनित हो गए हैं। जल्द ही इसका निर्माण शुरू होगा। जिले में मौजूदा समय पुलिस लाइन में स्थाई हेलिपैड हैं। अब तक वीआइपी दौरों के समय अस्थायी हेलिपैड बनाए जाते हैं। इसमें समय और धन बर्बाद होता है। स्थायी बनने से समस्या का समाधान हो जाएगा। साल में पांच से सात बार वीआईपी मूवमेंट होते हैं। चुनाव के दौरान वीआईपी मूवमेंट की संख्या बढ़ जाती है। इनके लिए अस्थायी हेलिपैड बनाए जाते हैं। स्थायी हेलिपैड बनाए जाने की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग को दी गई है। सरकार की नई नीति के तहत इसका निर्माण होगा। योजना का मुख्य उद्देश्य आपदा प्रबंधन, चिकित्सा आपात स्थितियों और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों सहित अन्य वीआईपी आगमन को सुगम बनाना है। जिले में डीघ ब्लॉक के सीतामढ़ी, भदोही के भिखारीपुर, औराई के काशिराज इंटर कॉलेज और ज्ञानपुर के सरपतहां में हेलिपैड बनाए जाएंगे। जल्द ही इसका स्टीमेट बनाकर शासन को भेजा जाएगा। बजट स्वीकृत होने पर निर्माण शुरू किया जाएगा।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक

श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0 – 7007415808, 9415034002

Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।